साइबर सुरक्षा :- साइबर हमले में 80% part भी चाइनीज

PAK — S/A → USA
NSA — चीन

सरकार की पहल :-

1) मोबाइल एवं इन्टरनेट कनेक्शन के संदर्भ में KYC नॉर्म का उपयोग
ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति को ट्रेस करना संभव

2) बिना इन्टरनेट कनेक्शन के भी use है :. साइबर कैफे के use हेतु ID प्रूफ पहचान की अनिवार्यता

3) सुरक्षा प्रणालियों का व्यापक विकास & use (फायर वॉल, anti वायरस सॉफ्ट वेयर आदि)

4) encrypted Signals के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहन (संकेत में) → वही sys track-जो कि इ. इ._ को Decode करने की क्षमता रखता है

⇒ 5) National स्तर पर सुरक्षा हेतु "राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति" को अपनाया जाना।

प्रस्ताव :-

1) - नोडल एजेंसी के गठन का प्रस्ताव ⇒ (राष्ट्रीय स्तर पर Cyber नीति)
(- जो इस area में हो रहे R&D पर निगाह
-)
जो साइबर सु० के लिए नियमित तौर पर कार्य करेगी।
(सामरिक, आर्थिक, व्यवसायिक, सैन्य, सरकारी)
विभिन्न संगठनों की सुरक्षा

2) राष्ट्रीय ICT (Information & Comunication Tech) की संरचना की सुरक्षा हेतु स्वीकृत दृष्टिकोण का विकास करना।

3) PPP मॉडल के आधार पर रा० सा० सु० व्यव का संचालन
इसमें R&D (अनुसंधान एवं विकास) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

4) ग्रैस आधारभूत ढाँचा के विकास हेतु 14 अलग-2 लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना।

5) अति imp संरचनाओं की सुरक्षा के लिए NCIIPC (National Critical Information Infrastructure protection Centre) के गठन का भी प्रस्ताव है।

→ सामरिक imp. के सभी क्षेत्रों एवं केन्द्रों के सा० सु० की नियमित निगरानी रखेगा ex:- नाभिकीय Centre, अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह एवं उसकी प्रणालियाँ, वायु नियंत्रण प्रणालियाँ।

↳ अन्य सार्वजनिक एवं निजी व्यवसायिक संगठनों की सुरक्षा।

⇓

Cert-In → (Computer Em Resp. Team)

⇓

आपातकालीन परिस्थितियों में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी

6) NCIIPC को NTRO (नेशनल Tech. research org.) के अधीन रखा जाएगा ↳ Technical Intelligence हेतु नोडल एजेंसी (तकनीकी जासूसी)

↳ कार्य :- तकनीकी जासूसी करना

↳ How :- उप० के High resolution कैमरा को नियंत्रित करके विदेशों में तकनीकी विकास पर निगरानी रखना। ⇒ MEO का use (गगन परि०)

7) साइबर सु० के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कार्यबल उपलब्ध करना। इसके लिए अगले 5 वर्षों में 5 लाख प्रशिक्षित work Force का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें सरकारी - निजि दोनों शामिल है।

8) साइ० सुरक्षा हेतु regulatory framework विकसित करना, जिसमें कानूनी प्रावधान भी शामिल होंगे।

आंतरिक सुरक्षा हेतु उत्तरदायी तंत्र

- बाह्य ⇒ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा ⇒ C
- आंतरिक ⇒ सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ - साथ अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा ⇒ C - S

जिम्मेदारी: C | C - S

सीमा सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन :-

1) सेना के तीन अंगों की उपलब्धता तथा एकीकरण के उद्देश्य से IDS (Integreated Defence staff) का गठन।

2) सेना को अत्याधुनिक अस्त्र - शस्त्र एवं प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना। ex :- प्रक्षेपास्त्र, नाभिकीय अस्त्र, उपग्रह सर्विलांस की सुविधा (सीमावर्ती क्षेत्रों के पूर्वेक्षण)।
⇓
DIPAC ⇒ रणनीति ⇒ फील्ड एजेंट की जानकारी

IRS की बोर्डर रेखिया — resource जानकारी — सीमा की खुफिया जानकारी

(3) सेना के सहायक के रूप में पैरा मिलिट्री forces की उपलब्धता → ex → a) ITBP → (भारत - तिब्बत (चीन) सीमा)
⇓
1990 के दशक में भूमिका विस्तारित

now use — security — आपदा प्रबंधन — नाभिकीय - जैविक - रासायनिक आपदाओं से निपटने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया है।

(b) SSBC (सशस्त्र सीमा बल) है भारत - नेपाल, भारत - भूटान सीमा → थल सेना को assist
जिम्मेदारी →

c) असम रायफल्स है भारत का oldest पैरामिलिट्री force

खतरा बहुत कम हुआ। किन्तु इस संदर्भ में भौतिक [illegible] व भूमिका राज्यों की है, अतः उनका भी पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए

राजनीतिक विचारधाराऐं

प्रश्न :- पूँजीवाद से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूप कौनसे हैं? विशेष रूप से समकालिन संदर्भ में पूँ० के नये रूपों की चर्चा करे।

प्र०(2) :- पू० का विश्व तथा भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? यह प्रभाव (+)ve है, या (-)ve

प्र० 3 :- साम्यवाद से आप क्या समझते हैं, इसका समाजवाद से क्या संबंध है।

प्र० 4 :- साम्य० से जुड़े निम्न० सिद्धांतों पर टिप्पणी करे —

a) ऐतिहासिक भौतिकवाद (b) आ० नियतिवाद (Determinism)

c) अधिशेष मूल्य का सिद्धांत (Theory of Surplus Value)

d) धर्म

प्र :- धर्म आम जनता के लिए अफीम है।

प्र० :- अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन तथा राष्ट्रवाद का विरोध

प्र :- अलगाव का सिद्धांत (T. of Alienation)

प्र :- क्रांति का सिद्धांत

प्र :- साम्यवादी विचारों में कार्ल मार्क्स के बाद प्रमुख संशोधन क्या हुए? प्रमुख विचारकों के नाम बताते हुए उनके योगदान पर विचार / मूल्यांकन करे।

प्र :- समाजवाद के विभिन्न प्रकारों पर विचार करे मुख्य रूप से फेबियन समाजवाद तथा लोकतांत्रिक समाजवाद का परिचय प्रस्तुत करे।

प्र :- श्रमाधिपत्यवाद क्या है, भारतीय पा०रे० मे इसका (Syndicalism) क्या imp. है।

प्र:→ नक्सलवाद या माओवाद से आप क्या समझते हैं, यह किस विचारधारा को अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि स्वीकार करता है।

प्र:→ उदारवाद क्या है, इसे पूँजीवाद का दर्शन क्यों कहा जाता है।

केवल नवउदारवाद के बारे में नहीं

प्र:→ नव उदारवाद क्या है, क्या यह कहना उचित होगा कि वर्तमान भारतीय अर्थ० नव० के सिद्धांतों पर ही टीकी है?

प्र:→ पूँजी० के निम्नलिखित प्रकारों पर टिप्पणी —

1) मुक्त बाजार पूँ० (Free Market C.) / अहस्तक्षेप पूँजी० (लैसेज फेयर C.)

(2) कॉरपोरेट पूँ / निगमीकृत

(3) कल्याणकारी पूँ० (welfare C.)

(4) क्रोनी पूँजीवाद (जुगाड़)

(5) रचनात्मक पूँजी० (Creative Capit.)

प्र:→ साम्यवाद का प्रभाव साम्यवादी देशों तथा विश्व पर क्या पड़ा? यह प्रभाव (+)ve है, या (−)ve

प्र० Same Ques. for समाजवाद

Clash of Civilization

15th — 20th Century
⇓
यूरोप का इतिहास

मार्क्स (Ist)

साम्य० पूँजीवाद समाजवाद

Feudalism (सामंतवाद) :- यूरोप की S-E० व्यवस्था.
⇓
// कृषि आधारित व्य०) 15th व 16th cent
⇓
टूटा
⇓
new ढाँचा ⇒ Capitalism

मार्क्स (मानता है, कि यह क्रम से change)
↓
F
↓
Cap
↓
Soci.
⇓
Commun.

for विकसित nation
I
↓
II
↓
III

सामंती विचारधारा
⇓
कृषि अर्थ० के केन्द्रित

Feuda.
→ ICOR कृषि > मनुष्य > मंत्र
→ भेदभाव → विधान के विभाजन
→ वैध
⇓
(सामंतवाद में भेदभाव को राज्य द्वारा स्वीकृत)

कृषि आधारित व्यवस्था

↓
जमीन पर
सामंत
बड़े सामंत शक्तिशाली
∴ F व्यवस्था

वैध
→ किसान
→ बेगार (force labour)
— अनिवार्य सैनिक सेवा
→ अधिकार कुसामंत

सामंत
→ Land के आधार पर आय अर्जित
→ बुर्जुआ (धन कमाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति)
↳ इन्होंने जिस पूँजी० का विकास किया
वह साहसिक पूँजीवाद
① (साहस पर आधारित)
② श्रम — विभाजन पर आधारित पूँजी
↳ cottage Indus
(Ex → मोची द्वारा काम
से ... तैयार

// mercantilism
नए क्षेत्रों की खोज + व्यापार

सामंत ने छोटी पूँजी

श्रम विभाजन से उत्पादकता ↑

मशीन के पूर्व की रूप

पूँजीवाद ⇒ ब्रिटेन में वैज्ञानिक क्रांति

↳ पूँजी का निवेश कर लाभ कमाने की Economy

मशीन आधारित पूँजीवाद → बड़े बुर्जुआ

↳ बड़ी मशीन + संख्या ज्यादा ↑

उत्पादन ↑ ⇒ लाभ ↑

बनाने वाले आधिक होते गए

• बिक्री > खरीददार ⇒ उपनिवेशवाद / ~~[illegible]~~ साम्राज्यवाद

म॰ भा॰ C

लेसेस फेयर C

अहस्तक्षेप

Freemarket Capi.

1) राज्य का अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं होता

2) वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय की सम्पूर्ण प्रक्रिया माँग व पूर्ति के नियमों के अनुसार पूरी होगी।

⇒ मुक्त बाजार का अर्थ है, ऐसा बा॰ जिसमें प्रवेश तथा बाहर निकलने हेतु प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। वह अपनी ~~क्षमताएँ~~, अपनी सेवाएँ या अपनी पूँजी के साथ बाजार में उतर सकता है। बाजार में उसकी उतनी ही माँग होगी, जितनी मात्रा में वह समाज हेतु उत्पादकता का सृजन करेगा। समाज की माँग के अनुसार उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं/से॰ का मूल्य निर्धारित होगा। वह जितना मूल्य प्राप्त करेगा,

वहीं उसके सामाजिक योगदान के बराबर होगा।

Welfare C. (कल्याणकारी पूँजी॰) :→ 1850 के आस पास

C. के कुछ समर्थकों ने मान लिया, कि पूँजीपति का कार्य केवल व्यक्तिगत लाभ कमाना नहीं है, बल्कि सामाजिक कल्याण में भी उसकी जिम्मेदारी बनती है। आज कल की भाषा मे इसे Corporate social responsibility कहते हैं। क॰ पूँ॰ के प्रमुख विचार निम्न हैं

1— सरकार बाजार को पूरी तरह नियंत्रित तो नहीं करेगी, पर इतना नियंत्रण अवश्य कर सकती है, कि पूँजीपति समाज को नुकसान ना पहुँचा सके।

2) पूँजीपति जितना लाभ कमाते हैं, उसी अनुपात में सरकार को उनसे कर वसूलना चाहिए, तथा कर से प्राप्त हुई राशि को वंचित वर्गों के कल्याण में खर्च करना चाहिए।

(3) निजी क्षेत्र को सरकार की उन नीतियों मे सक्रिय तौर पर हिस्सेदार होना चाहिए, जो S. न्याय या S. कल्याण के पक्ष मे चलायी जा रही हैं। (जैसे अमेरिका में "डायवर्सिटी" नीति या भारत में आरक्षण जैसी नीतियाँ ⇒ यह आज भी चल रहा है)

State C. :→ इसका अर्थ है, कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसी व्यक्ति या समूह का नहीं है, बल्कि राज्य का ही होगा इसे C. इ॰ कहते हैं, bcoz इसमें S. अपने उद्यमों को सिर्फ समाज कल्याण का माध्यम ना मानकर लाभ अर्जित करने का माध्यम भी मानता है। भारत सहित विश्व के कई देशों में सरकारें ऐसे उद्यम चला रही हैं।

छोनी C. :→ यह उदारीकरण के दौर में विकसित हुई नई अवधारणा है, इसका अर्थ है, बड़े उद्यमियों, औद्योगिक घरा-

तथा राजनीतिज्ञों के साथ अपने निकट संबंधों के आधार पर लाभ कमाना।
लोकतांत्रिक देशों में तथा देखा जा रहा है, कि बड़े औद्योगिक घराने कुछ मध्यस्थों के साथ मिलकर सरकार को इस तरह प्रभावित करते हैं कि सरकारी नीतियों के कारण उनका लाभ बढ़ जाये।
नीतियों में निम्नलिखित प्रकार के change हो सकते हैं:-

1) किसी विशेष उद्योग से संबंधित लाइसेंस उन्हीं उद्यमियों को देना, जिनसे ऐसा संबंध है। → (2जी स्पेक्ट्रम, कोलगेट)
2) किसी विशेष क्षेत्र को कुछ वर्षों के लिए tax से माफी दिलवाना या छूट। (Ex:- IT)
(3) किसी नीति में अपने मुताबिक संशोधन करा लेना। (Ex:-

निगमीकृत C. :-
कॉर्पोरेट C (C.C.) ← आया :→ ज्यादा पूँजी वाले I. की स्थापना हेतु
(i) व्यक्ति आधारित structure की तुलना में नियम आधारित structure
⇒ व्यक्तिगत परिवर्तन का no effect)

C.C :→ प्रमुखतः 20वीं शताब्दी की अवधारणा है, जब महंगी तकनीकों पर आधारित बड़े उद्यम खड़े करने हेतु पूँजी की जरूरत इतनी अधिक हो गई, कि एक व्यक्ति या एक परिवार हेतु ऐसे उद्यम की शुरुआत करना संभव नहीं रहा, ऐसी स्थिति में नया विकल्प यही था, कि बहुत सारे अपरिचित लोग मिलकर अपनी-2 पूँजी के योगदान द्वारा संयुक्त उद्यम की शुरुआत करें। मोटे तौर पर इसी व्यवस्था को CC कहते हैं।

लक्षण of C.C. :-

1) बड़ी पूँजी पर आधारित उद्यम
2) उद्यम का मालिकाना हक बहुत सारे शेयरों (shares) में विभाजित होता है।

(2) शेयरधारक स्टॉक एक्सचेंज या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से अपने अंश को जब चाहे बेच सकते हैं व जब चाहे तो किसी अन्य के अंश को खरीद सकते हैं।

(3) उद्यम की नीतियों का निर्धारण, वे व्यक्ति करते हैं, जिनके पास एक निश्चित मात्रा से अधिक अंश होते हैं।

(4) उद्यम के मूल संविधान में (या उस देश में प्रचलित विधि) के अंतर्गत यह तय होता है, कि कितने % अंश होने पर कौनसे अधिकार मिलेंगे।

(5) ऐसे उद्यमों का प्रबंधन चलाने हेतु एक पूर्णकालिक तथा प्रतिबद्ध अधिकारी तंत्र होता है, सभी विभागों का कामकाज मुख्यतः पारदर्शिता संबंधी कामकाज इस तरह किया जाता है, कि कोई भी शेयरधारक उसे जान सके।

बिल गेट्स ↓ 2008 world Economic forum → पूंजीवाद पर आरोप लगा, → पूंजीपतियों को समाज हेतु work. → उन्हें 50% of wealth को donate करना है → social उद्यम → गरीबों के हितैषी बनेंगे, कि गरीब भी आगे आयें → वर्कर्स ने इसे support किया।

group तैयार ↓ इस concept को Bill गेट्स ने नाम दिया कि रचनात्मक पूंजीवाद

रचनात्मक पूंजीवाद → यह अवधारणा 2008 में WEF के दावोस सम्मे० में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रस्तुत की। बाद में इसका समर्थन USA के कई बड़े पूंजीपतियों ने भी किया। जिनमें वारेन बफे तथा मार्क जुकरबर्ग शामिल हैं।

मूल्यांकन ✓ रचना० C. का अर्थ है, कि पूंजीपति को सिर्फ अपने लाभ हेतु ना सोचकर बड़े पैमाने पर समाज कल्याण के प्रयत्न करने चाहिए। अपना कर चुकाने से संबंधित सा० योगदान देने के अलावा उन्हें अपनी संपत्ति के बड़े हिस्से का उपयोग वंचित देशों या वंचित वर्गों के कल्याण में करना चाहिए। यह ~~किसी~~ प्रयास किसी एक उद्यमी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अधिकांश उद्यमियों को इसमें भागीदार होना चाहिए। ऐसा होने पर ही यह पूंजीवाद का नया रूप बनेगा।

बिल गेट्स ने घोषणा की कि वे अपनी कुछ सम्पत्ति का 50% लो० कल्याण में खर्च करेंगे। वारेन ब कई अन्य उद्यमियो ने भी इस शपथ पर हस्ताक्षर किये। उन सभी ने विश्व के कई C. की यात्रा करके। जिनमें भारत व चीन भी शामिल हैं, वहाँ के उद्यमियों को भी ऐसा करने हेतु प्रेरित किया।

विकासशील C० में अभी यह विचार पर्याप्त लोकप्रिय नहीं हो सका है। एक कारण यह है, कि इन देशों के उद्यमियों के पास तुलनात्मक रूप से कुल सम्पत्ति कम है। दूसरा यह, कि इन C० में बड़ी पूँजी का निवेश करने की ताकत कुछ ही उद्यमियो के पास है। अगर वे अपनी संपत्ति दान कर देंगे, तो पूँजी निर्माण का संकट पैदा होगा। जो इन देशों के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है।

टेक्नो० C० — पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान तकनीक में कई ऐसे विकास हुए हैं, जिन्होंने बड़े पूँजीवादी उद्यमों की स्थापना की है, मुख्य रूप से बायो टेक्नोलॉजी, सूचना-तकनीक, अंतरिक्ष अनुसंधान तथा ऊर्जा में ऐसे प्रयोग हुए हैं। नयी तक० पर आधारित उद्यम को स्थापित करने की प्रवृत्ति को ही T० C० कहते हैं। (उदा० :- बायोकॉन, सेलेरा जीनोमिक्स, डेल्फ्न, विप्रो)

वाणिज्यवाद है — Only trade
↳ कहीं से चीज को खरीद कर
अन्य जगह बेचना।

Liberty & Freedom

Liberalism (उदारवाद)

मार्क्सवाद दर्शन/भौतिकवाद का दर्शन → पूँजीवाद का दर्शन

C & L

Metaphysics (तत्व मीमांसा) है
↳ जगत की वास्तविकता की व्याख्या ⇄ कैसे बना
(ईश्वर/आत्मा/परमात्मा...)

वास्तविकता व्याख्या
→ एकवादी (अंतिम रूप से एक ही चीज)
→ द्वैतवादी
→ बहुलवादी

आस्तिक नहीं → एक ही भौतिक पदार्थ से प्राप्त

चेतना ← → भौतिक

भौतिक → चेतना

→ एकवादी के prob. की दोनों कैसे related

भौतिक वस्तु से चेतना
⇓
भौतिकवादी (Materialism)

मार्क्स भौतिकवादी

चेतना से भौतिक (पदार्थ)
⇓
प्रत्ययवादी / आदर्शवादी / विज्ञानवाद / अध्यात्मवाद
(Idealism) (Spiritualism)

महात्मा गाँधी आदर्शवादी

चेतना भौतिक दोनों साथ -?

प्रत्ययवादी → चेतन / ईश्वर
(गाँधी जी)
⇓
इसी ने जगत बनाया है।

मार्क्सवादी (Materialism) → मस्तिष्क भौतिक वस्तु
⇓
विचार का विकास

मार्क्स → किसी दर्शन को कभी का दर्शन ना माने
भौतिकवादी
हर दर्शन किसी एक वर्ग के पक्ष

उदारवाद :- 16th - 17th Century

स्थिति :-
- ✓ चर्च का प्रभाव था
- ✓ कैथोलिक - प्रोटेस्टेंट के संघर्ष
- ✓ राजा — निरंकुश प्रवृति
- ✓ सामंतवाद (सामंतों को विशेषाधिकार

(जिसके पास जमीन नहीं अन्य की जमीन पर कार्य।) अर्द्धदास → काम करना ही पड़ेगा।

पूंजीवादियों के सामने संकट
↓
मजदूरों की जरूरत ⇓ जो कि सामंतों के पास कैद
पूंजीपतियों पर कोई रोक टोक ना हो

(-)ve (+)ve

उदारवाद का उदारता है :- पारम्परिक / नकारात्मक L.

bcoz सबसे पहले उत्पन्न

Show व्याख्या मात्र का

व्याख्या क्षेत्री की क्या है और है

उसमें क्या नहीं व्याख्या

जो/उनी द्वारा मान्य ...

स्वाधीनता है – बंधनों का नहीं होना

Liberalism

⇓

नकारात्मक (?)

- व्यक्ति
- व्यक्ति-समाज
- राज्य
- अर्थव्यवस्था

व्यक्ति

- प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील
  ⇓
  स्वयं के बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्णय
- आजादी की बात (राज्य से मुक्ति)
- Possessive Individualism (स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद)
  ↳ व्यक्ति का अपने शरीर, बुद्धि व दोनों के प्रयोग से प्राप्त लाभ (?) पर नैतिक अधिकार

why bcoz माना गया है, कि वह अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकता है।

यदि कोई पूँजीपति पैसा ज्यादा कमाता है ⇒ उसे अनैतिक नहीं माना ⇓ बेंथम नीति (?)

व्यक्ति-समाज

⇓

- दौड़ / प्रतिस्पर्धा
  ↳ प्रतिस्पर्धा के नियम निश्चित
  ⇓
- परिणाम के स्तर पर चाहे असमानता पैदा हो, कोई प्रभाव नहीं
- समाज के बंधनों (धर्म, जाति, बिरादरी) bcoz से मुक्ति मिले।
  अतः Condition में बाधक बन सकते हैं।

राज्य

- Minimal state (न्यूनतम राज्य)
  ↳ राज्य केवल उतना ही हो जितना न्यूनतम जरूरी
  ⇓
  only
  सुरक्षा / प्रतिस्पर्धा को नियम
  (नाइट वाचमैन स्टेट)

अर्थव्यवस्था

- → अहस्तक्षेप (लैसेज फेयर)
- → Free market Economy
- → (Demand & Supply)
- → freedom of Contract
  ⇓
  किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं
  निर्वाह मजदूरी
  ⇓
  उतनी मजदूरी जिससे केवल निर्वाह

⇒ 19th Century में — — —

(1800-1830) आरंभिक समाजवाद / स्वप्नदर्शीय S. (by कार्ल मार्क्स) / यूटोपियन Socialism

by सैंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर, रॉबर्ट ओवन

⇒ मजदूरों की स्थिति खराब ⟹ सुधार चाहते हैं।

- अंतरात्मा को बदलना
- शांतिपूर्ण तरीके की बात

समाजवाद — समाज में धन का वितरण न्यायपूर्ण हो

1818 ⇒ मार्क्स → लोकतंत्र को खारिज
(believed workers) — bcoz यह पूँजीपतियों का शासन

1844 — हिंसक क्रांति का सिद्धांत

- पूँजीपति की अंतरात्मा change नहीं
- भौतिकतावादी
  - भौतिक स्थिति पूँजीपतियों को अनुकूल
  - ∴ विचार change नहीं
  - ⇓ पूँजीवादी परि० को बदलना / C. को समाप्त
  - ⇓ throw हिंसक क्रांति

मार्क्सवाद को समाजवाद का ही प्रकार
- समा. का वह रूप जो हिंसा पर बल

⇒ 1848 → यूरोप में कई क्रांतियाँ
(माना जाता है, कि मार्क्स के विचारों का प्रभाव)

⇒ 1850 ⇒ J. S. मिल
- प्रारंभ में नकारात्मक उदारवादी
- बाद में (+)ve liberalism
- ⇓ मार्क्स को जरूरत से ज्यादा आंकना
- new theory (+)ve liberalism
- ⇓ फेबियन समाजवाद निकला
- ⇓ इंग्लैंड में अधिक प्रचलित
- effect

1860–65 → C. war → दास प्रथा समाप्त करने हेतु → उत्तर दक्षिण USA के अलग
- ⇓ C. दास व्यवस्था समाप्त
- अमेरिका की सफलता → लोकतंत्र

=>

(+)ve Liberalism

welfare Capitalism

~~राज्य कल्याणकारी~~

welfare estate

Progression

Tax

→ जैसे :- आय बढ़ेगी ⇒ Tax भी बढ़ेगा

मिल

Private Property होनी चाहिए

○ संपत्ति के

Affirmative Action (सकारात्मक कार्यवाही)

⇓

○ Social Justice

⇓

○ Protective discrimination

○ social engineering (सामाजिक अभियांत्रिकी)

[illegible] उदाहरण, सामंतों से ~~[illegible]~~ जमीन ले गरीबों को बांटने

social Justice को लाने के तरीके
- ○ आरक्षण
- ○ Preference

○ Aff. Action :- W. State को केवल कानून नहीं बल्कि वंचितों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास

○ Protect Dis :- ऐसा भेदभाव, जो वंचित वर्गों के संरक्षण हेतु किया जाये

○ Social Justice :- समाज के जो समूह अन्याय की दशा में है, उन्हें न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया

○ सोशल इंजीनियरिंग :- ऐसे विशेष उपाय करना, जिनसे समाज को मनचाहा रूप दिया जा सके।

20th cent.

1950

उदारवाद

Liberterianism (स्वेच्छातंत्रवाद)

same → Neo-liberalism (नव-उदारवाद)

⇓

नकारात्मक approach

क्योंकि (-)ve

Liberalism की

- welfare estate का विरोध ⇓

इस समय concept

(-)ve + LPG

⇒ नव उदारवाद

Equalitarianism

Eg (समतावाद)

⇓

(+)ve Like

(theory of Justice) ⇑ जॉन रॉल्स

→ C. B. मैकफर्सन

LPG — उदारवाद

नकारात्मक	सकारात्मक
- समानता का अर्थ है, विषमताओं या भेदभाव का ना होना।	- समानता का अर्थ है, ऐसी स्थितियों का होना, जिसमें सभी व्यक्ति लगभग समान सुविधाओं का भोग कर सके।
- स्वतंत्रता का अर्थ है, परतंत्रता का होना, अर्थात अगर किसी को बांध कर नहीं रखा गया है, तो वह स्वतंत्र है।	- स्वतंत्रता का अर्थ है, ऐसी स्थितियों का मौजूद होना, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी सके।
- न्याय का अर्थ है, कानूनों के स्तर पर भेदभाव का ना होना व विभिन्न व्यक्तियों के लिए एक जैसी अदालती व्यवस्था का होना।	- न्याय का अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय की पहुँच का बराबर होना। वंचित वर्गों के लिए विशेष उपाय करना; ताकि वास्तविक रूप से न्यायपूर्ण दशाओं में वे

समाजवाद — साम्यवाद

विचारधारा I) — एक व्यापक विचारधारा
(अर्थात् सामान्य विचार)
आर्थिक संसाधनों का समतामूलक वितरण।

अवस्था — मार्क्सवाद में पूँजीवाद के बाद की अवस्था (इसी अवस्था को सर्वहारा की तानाशाही भी कहते हैं।)

— विकासवादी समा० (Evolutionary) या स्वप्नदर्शी S ⇒ (अर्थात् वे समाजवाद, जो हिंसा पर नहीं अहिंसा पर बल देते हैं।)

साम्यवाद

विचारधारा II) — एक निश्चित विचारधारा → (हिंसा पर बल देने वाला समाज)
(अर्थात् एक या दो व्यक्तियों के नाम से)
इस का रूप ⇒ मार्क्सवाद

अवस्था — मार्क्सवाद में समाजवाद के बाद की अवस्था
(सर्वहारा की तानाशाही के बाद की अवस्था, जिसमें राज्य नहीं रहता है।)

Diff b/w समाज० व साम्य०

I) ~~समाजवाद~~ साम्यवाद समाजवाद का एक part है।

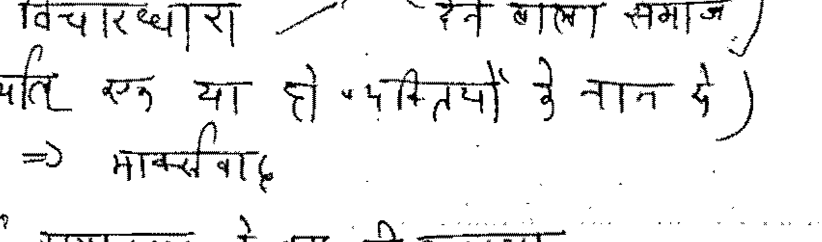

ii) समाज० से मार्क्स अवस्था साम्यवाद

अगर मार्क्सवाद के तहत देखें, तो

पूँजीवाद → समाजवाद → साम्यवाद

कार्यपद्धति III) अगर समाज० का अर्थ क्रियात्मक समा० से लें, तो और साम्यवाद का अर्थ विचारधारा से लें, तो समाज० व साम्य० व विरोधी विचारधारा, ∵ समाज → शांति पर जबकि साम्यवादी → हिंसा पर बल

Note :- अभी किसी भी देश में अवस्था के रूप में साम्यवाद नहीं आया है।

और साम्यवादी → अवस्था → विचारधारा

⇒ जहाँ तक साम्यवादी अवस्था का प्रश्न है, वह अभी तक दुनिया के किसी भी देश में नहीं आयी है, ∴ किसी भी देश को जब साम्य० कहा जाता है, तो इसका इतना ही अर्थ है, कि वह देश घोषित तौर पर मार्क्सवाद का अनुसरण करता है।

मार्क्सवाद / क्रांतिकारी समाजवाद / साम्यवाद / वैज्ञानिक समाजवाद

मार्क्सवाद ⇓ क्योंकि मार्क्स ने दिया

क्रांतिकारी समाजवाद ⇓ (Revolutionary) मार्क्स ने कहा ⇓ दो विचारधारा में अंतर

(Revolutionary) → throw हिंसा

विकासवादी समाजवाद (Evolutionary) ⇒ (लोकतांत्रिक तरीके से धीरे-धीरे समाजवाद)
↳ by बर्नस्टीन

साम्यवाद → अंतिम target ⇒ जिसे मार्क्सवाद प्राप्त करना चाहता है।

वैज्ञानिक समाजवाद → by मार्क्स
fore-कल्पनावादी समाजवाद से अलग करने हेतु
→ यूटोपिया की सोच वास्तविक नहीं ⇓ उसे काल्पनिक कहा

मार्क्सवाद ⇓ Metaphysics ⇓
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद (Dialectic Materialism)
⇒ मार्क्सवाद का आधार
इसके आधार पर मानव समाज व भूत - वर्तमान - भविष्य की व्याख्या

→ इस व्याख्या का नाम ऐतिहासिक भौतिकवाद (H.M) → हमारी दुनिया H.M. का ज्यादा प्रभाव

भौतिकवादी → परलोक में विश्वास नहीं
→ इस जगत के परे कुछ नहीं

द्वंद्वात्मक → कोई भी विकास द्वंद्व से होता है।
↳ मार्क्स ⇓ हीगल / द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया
हीगल का विचार द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद ⇒

(द्वंद्वात्मक तथ्यवाद)

(Dilectic Idealism)

मार्क्स & हिगेल में सहमति
⇓
on द्वंद्वात्मक

19th C. ⇒ विज्ञान का usage
⇓
निरपेक्ष व्याख्या

H.M.

जब मानव समाज का अध्ययन

1) बुनियादी ढाँचा

बुनियादी ढाँचा ⇓ उत्पादन प्रणाली

ऊपरी ढाँचा → (शेष चीजें in समाज)

like → I.R., culture, Polity, Society etc

अर्थव्यवस्था (Mode of Production)

Economic Determinism

Condit → Economy → प्रभाव on (100%) → ऊपरी ढाँचा

D-structure superstructure को निर्धारित करता है।

(2) Mode of Production है दो चीजों का संयोग है — MOP

I) Forces of Production (उत्पादन की शक्तियाँ)
⇓
किसी समाज का कितना विकास इस बात पर निर्भर कि व्यक्ति की भागीदारी कम

animate Energy → पशुओं की ऊर्जा का प्रयोग

→ उत्पादन प्रक्रिया में ...

II) Relation of Prod. (उत्पादन के संबंध)
→ अनिवार्य R. ⇓ Division of labour
→ शोषण R.

शोषण :- समाज में ऐसी घटनाएँ
⇓
असमानता

⇒ Human < Resource
Scarcity / अभाव ⇒ उत्पन्न ⇒ शोषण है ⇒ (जबरदस्ती उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण)

⇒ उच्च वर्ग → नेटवर्क → सम्पत्ति
⇓
मध्य वर्ग

⇒ मार्क्स :- उत्पादन की शक्तियों पर मालिकाना हक
⇓
बटवारा नहीं कर पाते
Haves ⇒ राज्य —— Have not
खड़ा

1960 ⇓ इन्टरमेन्स theory

→ शोषण ।
— समाज को दो ही वर्ग — Have → उत्पादन शक्ति का मा
— Have not " " नहीं
→ सम्पत्ति का बंटवारा असमान
⇓
ढाँचे को बदलने की जरूरत

I & II change ⇒ M.O.D. change
⇓ सामंतवाद / पूंजीवाद → विवाद
⇓ पूंजीवाद / समाजवाद
क्रांति

द्वंद्व विधि

वाद (T) ⟷ प्रतिवाद (AT)
⇓ संवाद

वाद (T)	संवाद	प्रतिवाद (AT)
Thesis	दोनों के समझौता	Anti thesis
पहले से स्थापित ढाँचा (नहीं माना)		विरोधी विचार (अन्ना हजारे → CBI / लोकपाल विधेयक)

द्वंद्व —— यदि → तानाशाह

⇓
बातचीत
(दोनों की बातें शामिल)

संवाद :- वाद – प्रतिवाद के बीच समझौते की

डीस्फती → संवाद स्थाति नहीं bcoz वह अब वाद →
new नया प्रतिवाद

(वाद) ⇌ (प्रति)
संवाद → T → AT
संवाद ⇒ T → AT
संवाद

हीगेल/मार्क्स दोनो कहते हैं
यह प्रक्रिया एक बिन्दु पर रुकेगी

मार्क्स ने 6 अवस्थाएँ बताई — (इतिहास)

मार्क्स → इतिहास का हर चरण पूर्व की तुलना से बेहतर

Pre Historic → ① आदिम साम्यवाद ⇒ (मार्क्स → इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास)
↓
चूँकि no वर्ग संघर्ष
पूरी समानता है
गरीबी → natural / कृत्रिम
↓
(कष्टपूर्ण जीवन)
→ बराबरी नहीं

History ② Age of Slavery
③ feudalism
④ Capt.
⑤ Socialism
⑥ Communal

राज्य है बताया जाता है
no slave की संपत्ति no not राज्य ना संघर्ष

② Age of Slavery है → मालिक
→ दास
→ दास मालिक की संपत्ति (→ आगे वाली पीढ़ी पर भी अधिकार)

③ सामंतवाद है → जमीन के मालिक
→ और कृषक
→ पहले के दासों से बेहतर स्थिति

④ पूँजीवाद → बुर्जुआ
→ मजदूर
→ मार्क्स कहता है, कि इसमें क्रांति की बड़ी संभावना
bcoz → मजदूर काम के बाद अपने घर (slum)
एक जगह ⇒ संवाद

⑤ समाजवाद है
(self enlightment stage के राज्य की जरूरत है।
→ सर्वहारा की तानाशाही / राज्य रूपी

मजदूरों की तानाशाही
(लोकतंत्र)

मार्क्स कहता है कि लोकतंत्र ⇒ तानाशाही

मजदूरों की तानाशाही ⇒ is a real लोकतंत्र
⇓
मार्क्सवादी ठोस लोकतंत्र
(Concreate Democracy)

प्रतिक्रांति
(1) ⇒ (कुछ व्यक्ति जो क्रांति के समय हिल गये थे)
⇓
नाहीं जनता को शोषण करेगी
: राज्य होना
जरूरी है

(2) प्रतिक्रांति → राज्य control
→ निजि संपत्ति समाप्त था. मन
→ धर्म

(क्रांति होते ही राज्य... धीरे-धीरे समाप्त...)

राज्य

विचारधारा ⇒ मिथ्या चेतना
(Ideology) (false Contiousness)

मार्क्स → अमीर अपने नियंत्रण को बनाये रख सके।
⇓
विचारधारा का प्रयोग → राज्य

समाजवाद ← विचारधारा
परिवर्तन ← शिक्षा
← धर्म
← राष्ट्रवाद
← लोकतंत्र/नैतिकता
} शोषण बातें स्वाभाविक नहीं

अमीर लोगों के गरीबों पर शोषण की व्यापार्थी

(मार्क्सवाद)

→ राज्य का अस्तित्व बिल्कुल खत्म

→ धर्म है → मानवीय चेतना से विलुप्त

→ प्रत्येक व्यक्ति क्षमता से

काम → जितनी काम उतना ही

वेतन मिलेगा |

→ काम रुचि से

→ जरूरत से वेतन

value addition
↳ वस्तु के मूल्य में वृद्धि

- Surplus value
- (अधिशेष मूल्य) ⇒ है → पूँजीपति का लाभ
मार्क्स — चोरी

→ factors

Land - Rent
Labour - वेतन
Capital

⇒ प्रॉफिट

(मार्क्स)
↳ फ्रॉड सब भी है
Rent : अवैध कमाई है
Capital भी खाली है
- और खतरा नहीं
→ तीन कारक काल्पनिक
सिर्फ मजदूर

(एडमस्मिथ)
जितना नैतिक उत्तर
तीन चीज कमाना जितना नैतिक
है, उतना ही लाभ

Ex 10/- 10/- → wages ⇒ 30 लाभ
↓ Rent+ 10 Market में 70
उत्पादन Interest 100 में बेचा

100 - 30 = (70)

100 - 20 ⇒ 80 वेतन should be

↳ This is अधिशेष चोरी

(—)
- पूरा लाभ मजदूरों
को देना मुश्किल
- देश में बाजार में बाधा

Allination है जो आप हैं, जैसा आप थी रहे हैं, उनके बीच अंतराल | Modern time

→ by हीगेल
→ अपने-आप को ईश्वर का अंश नहीं मानना
→ खारिज by मार्क्स

Human being है → creativity
→ वर्ग
→ परमार्थ
→ 6 इंद्रिया use 5
(V)^{mn}

इमाानिज → मूलतः कामचोर है

मार्क्स → मूलतः काम करना चाहता है।
- मनुष्य स्वतंत्र तो अपनी पसंद का का०
- मनुष्य मूलतः रचनी
- स्वार्थ मनुष्य पर थाही गयी प्रवृत्ति है।
- मनुष्य सबसे ज्यादा तब खुश जब उसकी creativity ... hc oz of Exchange economy (वस्तु विनिमय)

धर्म made by Human लेकिन जब यह इंसान को बाजार से बांधा हुआ

धर्म
पूंजीपति
Capitalism
मजदूर

मजदूर → Division of labour → specified → काम की रोचकता कम
→ Product पर कोई
→ साथियों के साथ Social
→ Human Nature रचनात्मक

समाकलन → साम्यवाद → division of Labour
→ Creativity

चर्चा :

हाथ की चक्की सामंतवाद — भाप का इंजन
↓ कृषि — ↓ औद्योगिक व्यवस्था
↓ जमीन का Imp
(उत्पादन व्यवस्था में मनुष्य की भूमिका ज्यादा)

⇒ Post industrial Capitalism →
→ संजय (?) बन्दरगाह
→ है ↓ आपनी मौत मरेगा
market demand ↓ → compitation ↑

कुछ पूंजी के पास पैसा ↓ ⇒ निवेश ज्यादा नहीं
मजदूरों की ज्यादा ⇒ रोजगार नहीं ⇒ असंतोष

(1960) ⇒ स्वाधीन
↓
पूंजीवाद ↑ पूंजीपति ↑ बाजार ↑ D < S
↓
(पूंजीवाद का सबसे बड़ा दौर)

मार्क्सवादियों का अनुमान था, कि इसके बाद पूंजीवाद खत्म
↓
Consumerism capitalism / late Cap का जन्म → विज्ञापन

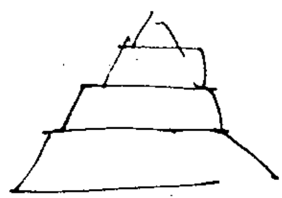

⇒ Demand create कर पूंजीवाद का विकास 1870
जर्मन - फ्रांस
1860 → USA

मार्क्स → Classical, NEO

Classical → L, S, n

↳ इस बात पर अवधारणा मार्क्स का रास्ता सही नहीं
⇓
०; मार्क्स है लोकतंत्र के माध्यम से भी साम्यवाद की स्थापना

1865 – 1915 तक
लगने लगा की क्रांति की जरूरत नहीं
⇓
नई विचारधारा का सिद्धांत विकास
⇓
1910 के आस-पास ⇒ NEO - मार्क्स. का विकास

⇒

1917 की घटना मार्क्सवाद का सामर्थन या विरोध

Que. लेनिनवाद → (मार्क्स) की तुलना | मार्क्स के अनुसार पहले पूंजीवाद का विकास

लेनिन - सामंतवाद के खिलाफ
० जनता पर इन भावना
→ जिस देश में साम्राज्य है, वह शक्तियां का रही एक का हैं।
० communist → सारे मजदूर वर्ग मध्यम वर्ग किसान
hardly... → शोषित व्यक्तों का concept ... → की imp

किसी वर्ग की वस्तुगत स्थिति → उनकी चेतना निर्धारित
ट्राटस्की vs स्टालिन

स्टालिन है स्टालिन
↳ Ideological हत्या
→ भारत भारत, चीन के हार
→ एक देश में समाजवाद का सिद्धांत दिया
→ राष्ट्रवाद बहुत बुरी चीज नहीं
→ राज्य शायद अभी खत्म नहीं

माओ
→ राष्ट्रवाद
→ किसान
→ निरंतर क्रांति
→ सांस्कृतिक क्रांति (C.R)

सांस्कृतिक क्रांति में

क्रांति के साथ ही सोच नहीं बदलेगी

माओ ने इस चीज को समझा

→ क्रांति तब तक चलेगी जब तक सब की मानसिकता पूरी तरह नहीं बदले

— राज्य जब तक क्रांति तब तक रहेगा।

समाजवाद

↳ व्यापक विचारधारा

प्रकार
↳ utopian
↳ मार्क्स
↳ विकासवादी / विकासात्मक

- ऐंजेल्स
- ...
- विवाद चलने का कारण

1863 पुरुष को अपनी सम्पत्ति पुत्र को देनी है।

good व्यवस्था → no सम्पत्ति → no विवाद है

R. फ्यूरियर → Iron — Theory → मजदूर को उतना ही वेतन जितना मिले

सम्पत्ति नहीं — विवाह नहीं

Co-operative (सब मिलकर काम) ↳ सहयोग की भावना

पर्वत

विकासात्मक

- हिंसा पर बल नहीं
- राष्ट्रीयकरण पर बल

Syndicalism
↳ हिंसा स्वीकार
↳ मालिकों को बर्बाद
- आम हड़ताल की बात
- गुर्दे लाल कृति
- भारत में नक्सल

फेबियन

फेबियन समाज है → पूँजीवाद के विरुद्ध आक्रामक रूप नहीं
↳ व्यक्ति के नाम पर
↳ ऐतिहासिक w.
↳ जब तक सही मौका नहीं पर्चे

समाज में जागरूकता
⇓
लेबर पार्टी का जन्म
⇓
लंदन स्कूल of इको

- Spiritual Socialism
- Functional Federalism
- Collectivism

> आध्यात्मिक — केवल सांसारिक जगत तक सीमित नहीं
> → पूरे ब्रह्माण्ड के साथ संबंध

नरेन्द्र देव

भगवान का सहारा लेकर समाजवाद की बात करती

वेदांतिक समाजवाद
→ वेदांत के base पर समाजवाद की

अपरिग्रह → ज्यादा संसाधन स्थापना इकट्ठे नहीं करते

गाँधी
↓
direct election
Only गाँव के स्तर पर → पंचायत 5 (1.0)
→ only यहीं ही वोट

(प) 5th level
↑
(पंचायत) 5 cen Govt

functional Federalism — हमारा संघवाद त्रिस्तरीय है

Functional Federalism
ओडिशा → पीरामिड (1.0)

ऊपर — सत्ता — नीचे

काम का बँटवारा according to स्तर

केन्द्र पर नजरिया
→ सब पर

Collectivism है
→ किसी चीज का मूल्य बढ़ाने में समाज की भूमिका
मूल्य निर्धारण हेतु समाज उपकरण → राज्य
State सारी शक्तियों को manage करे

Syndicalism (श्रमाधिपत्यवाद / श्रमसंघवाद) है →
→ फ्रांस में मार्क्स को support
1785
↓
नकारात्मक अराजकवाद

- मजदूरों द्वारा अधिकारों की माँग →

=> 1920 क्रांति

श्रम संघवाद, फ्रांसिसी श्रम संघ S.M. से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ। यह फ्रांस की विशेष परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम था। वैचारिक स्तर पर इस पर कुछ प्रभाव मार्क्स का था, व कुछ प्रूधों का। यह Mo श्रमिक के द्वारा स्वतः विकसित हुआ, आगे चलकर कुछ विचारकों ने इसके सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या की। जिनमें जॉर्ज सोरेल सबसे प्रसिद्ध हैं।

F. में मजदूरों को वैसे अधिकार नहीं मिल सके थे, जैसे इंग्लैंड में मिले थे। 1789 की क्रांति का लाभ सिर्फ व्यापारियों व पूंजीपतियों को मिला था, मजदूरों को नहीं। 1803 में मजदूरों को हड़ताल के अधिकार से वंचित किया गया। 1804 में तो 20 व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी पाबंदी लगा दी गयी। 1860 के बाद मजदूरों को कुछ अधिकार देने की बात उठी, किन्तु 1871 में क्रांतिकारी उथल-पुथल के बाद मजदूर संगठनों को बुरी तरह कुचल दिया गया।

इसके बाद मजदूरों को चोरी-छुपे मिलकर ही अपने संगठन बनाना पड़ता था। इन संगठनों को Syndicate कहा गया व इन्हीं के नाम से Syndicalism या श्रम संघवाद नाम प्रचलित हुआ।

श्रम संघवाद की विचारधारा :-

1) यह Mo राज्य का विरोधी है। इनकी मान्यता है कि S. पूंजीपतियों के उपकरण की भांति कार्य करता है। प्रमाण यह है, कि जो सेना राष्ट्र सुरक्षा के लिए है, वहीं पूंजीपतियों के ...

माना इंग्लैंड के श्रेणी समाजवादियों (Guild S.) पर श्रमसंघवाद का प्रभाव माना जाता है।

भारत के नक्सलवादियों पर प्रभाव

- छापा मारने की पद्धति
- सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना
- S. का निषेध
- हिंसा को उचित मानना

श्रेणी समाजवाद (Guild S.)

एक व्यवसाय के करने वाले ... का समूह
कार्य → व्यक्तियों के परिवारों के ... हितों का संरक्षण

1) इंग्लैण्ड में श्रमसंघवाद सफल नहीं हुआ, क्योंकि हिंसा तथा क्रांतिकारिता पर आधारित विचारधाराएँ तथा इंग्लैण्ड के समाज में नहीं चल पाती। किन्तु श्रमसंघवाद का यह लाभ जरूर हुआ कि फेबियनवाद और समष्टिवाद, जो धीमी गति से तथा उदार परिवर्तन की माँग कर रहे थे, कि कमजोरियाँ सामने आ गये। 1915 से 1925 के बीच इंग्लैं. के श्रमसंघों ने एक Move. चलाया, जिसे श्रेणी समाज. कहा गया। इस M. का कोई विशिष्ट विचारक नहीं था, किन्तु हॉब्सन व कोल (Kohl) जैसे विचारकों को इसकी चर्चा मिलती है।

विशेषताएँ :- G. S. के अनुसार S. के भीतर G. को स्वशासित इकाइयों की तरह कार्य करना चाहिए।

संगठन थे, जिसमें एक व्यापार से जुड़े सभी लोग आपसी हितों
के संरक्षण हेतु संगठित होते थे। एक उद्योग में लगे हुए
सभी लोग चाहे वो मजदूर हो या बौद्धिक श्रम करने वाले,
वे सभी G. का हिस्सा होते हैं। और केवल व्यवसायिक
होते, बल्कि अन्य सामाजिक हितों तथा उत्तरदायित्वों
की पूर्ति भी करते हैं।

(2) प्रत्येक व्यवसाय का एक G. होगा, तथा G.
उस सम्पूर्ण व्यवसाय पर नियंत्रण होगा। इस
व्यवस्था में कोई पूँजीपति नहीं होगा।
उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व
राज्य के हाथों में होगा। पर अन्य
क्षेत्रों में उनका नियंत्रण गिल्डों के हाथों
होगा। गिल्ड के सदस्य ही तय करेंगे,
उत्पादन कितना, कब व कैसे करना है।

(3) G. S. केवल उत्पादकों को imp. नहीं देता,
उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखता है।
बिन्दु पर वह श्रम संघवाद से अलग है। उ.
मानना है कि कोई ऐसी व्यवस्था जरूर होनी
चाहिए, जो गिल्ड की ज्यादतियों से उपभोक्ता
की सुरक्षा कर सके। साधारणतः यह दायित्व
को देने पर सहमति है।

(4) G. S. के कुछ चिंतक S. के विरोधी हैं, but अधि

हड़ताल की है, जिससे समाज का जीवन ठप्प हो जाए, तथा राज्य व पूँजीवाद बेकार हो जाए। ऐसी हड़ताल में कारखानों के साथ-साथ हर विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

आम हड़ताल के अलावा मजदूरों को तोड़फोड़ (Sabotage) का प्रयोग करना चाहिए। इसके अंतर्गत गुरिल्ला या छापामार w. नीति का प्रयोग किया जायेगा। कारखाने की महँगी मशीनों को नुकसान पहुँचाना। कारखाने के उत्पादों में कोई खराबी पैदा कर देना, काम को धीरे-धीरे तथा कम मात्रा में करना, बाजार में अपने ही कारखाने के उत्पादों की छवि खराब कर देना- इत्यादि इसके तरीके हैं। सोरेल इन उपायों को अनुचित माना but S. की मुख्य धारा इसे स्वीकार करती रही है।

श्रमसंघवाद 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद ~~अचानक~~ सक्रिय हो गया 1920 में (May) पूरे फ्रांस में एक आम हड़ताल आयोजित की गयी। जिसने जनजीवन को ठप्प कर दिया। किन्तु अप्रत्याशित रूप से पूरे F. की जनता इस M. के विरुद्ध एकजुट हो गयी। जिससे यह विफल हो गया। इटली, स्पेन पर इसका काफी प्रभाव पड़ा। ... थोड़ी बहुत

move. की भी कुचलती हैं। ये मार्क्स के इस विचार से सहमत हैं, कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता।

2) S. राजनीतिक दलों का विरोध करता है।

3) दल एक कृत्रिम संगठन है, जो विचारधारा पर टीका होता है। और विचारधारा को आसानी से बदला जा सकता है। इसके विपरित वर्ग एक वास्तविक समूह है। जिसकी आ० स्थितियाँ व जीवन स्थितियाँ समान होती हैं। ∴ मजदूरों को राज० अखाडे में आये बिना अपने स्तर पर ही संघर्ष करना चाहिए।

3) समाजवाद की स्थापना हेतु क्रांति अनिवार्य है, और यह क्रांति राजनीति के स्तर पर नहीं अर्थ० के स्तर पर होगी। मानव S. मूलतः उत्पादकों का समाज है, उपभोक्ता का नहीं। और चूंकि उत्पादक मजदूर है, ∴ सम्पूर्ण अर्थ० व्यवस्था पर मजदूरों का नियंत्रण होना चाहिए।

(4) क्रांति Syndicates के माध्यम से होगी। Syndi. वर्ग संघर्ष में श्रम संघ की सेना की भांति कार्य करते हैं। पूंजीपतियों से बातचीत / समझौता करना समय की बर्बादी है। श्रमसंघों को छोटे-मोटे सुधार नहीं - आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा, और यह तभी संभव है, जब बिना मध्यस्थों के मजदूर स्वयं कार्य० करे।

(5) कार्यवाही का main aim है, आर्थिक क्षेत्र के पूंजीपति की कमर तोड़ देना। इसके लिए हिंसा अनिवार्य नहीं है। किन्तु आवश्यकता हो तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए। कार्य० के साधनों में सबसे प्रमुख है हड़ताल। हड़ताल का अर्थ

का अस्तित्व बने रहना जरूरी है, कुछ [illegible]
जो S. ही कर सकता है. जैसे:- शि०, स्वास्थ्य, परिवहन
J. S. etc. इसी प्रकार यदि दो या अधिक G. में
संघर्ष हो, तो अधिनिर्णयन (Adjudication) भी राज्य ही
कर सकता है। G. कुछ मनमाने पन से अल्पसंख्यकों की
रक्षा करना भी S. का एक कार्य होगा।

(5) G. S. हिंसा का प्रायः अस्वीकार करता है।

__निष्कर्ष__ :- 1915 के आस-पास England में G. S. के कुछ सफल प्रयोग हुए। उदा: के लिए भवन-निर्माण से संबंधित G — National Building G. ने इंग्लैं० के 20 शहरों में सस्ती दरों पर मकान बनाये जिनके बारे में माना गया, कि वे पूंजीपतियों द्वारा निर्मित मकानों की तुलना में सस्ते ही नहीं गुणवत्ता में बेहतर भी थे। कुछ और क्षेत्रों में भी ऐसे प्रयोग हुए, किन्तु सरकार की [illegible] ना मिल पाने के कारण और पूंजी० के विरोध के कारण यह M. विफल हो गया।

पूँजीवाद के प्रभाव

(+)ve

1) यह मनुष्य के मनोविज्ञान के अनुकूल है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा तभी मिलती है, जब उसके स्वार्थ संतुष्ट होते हैं। पूँजी० मनुष्य की मूल प्रवृत्ति को उत्पादकता से जोड़ता है।

2) उत्पादन में तीव्र वृद्धि

3) विशेषीकरण के कारण उत्पादकता ↑ व उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि।

4) S. & T. का तीव्र का विकास तथा उसके माध्यम से भी उत्पादकता व उत्पादन में वृद्धि।

5) अनुबंध की स्वतंत्रता के कारण मजदूरों को उस शोषण से मुक्ति मिली, जो सामंत के अधीन बेगार तथा अनिवार्य सैनिक सेवा के रूप में होता था।

6) व्यक्तिगत स्वतंत्रता का imp बढ़ा तथा धर्म व सामाजिक दबावों का imp कम हुआ।

7) राजनीतिक स्तर पर राजतंत्र की समाप्ति तथा लोकतंत्र के विकास में पूँजी० ने सहायता की।

(-)ve

1) उपनिवेशवाद + सा० में भारी वृद्धि हुई। (भारत का भी शोषण हुआ)

(2) पर्यावरण व प्रकृति को भारी नुकसान हुआ

(3) (पूँजीवाद की सफलता हेतु बाजार का विस्तार होना जरूरी है) यह विज्ञापनों के माध्यम से माँग भड़काता है, हर माँग को पूरा करने हेतु कच्चे माल के तौर पर प्रकृति का शोषण होता है। (सम्पूर्ण जीवजगत को भी नुकसान पहुँचता है)

(4) समाज में सहयोग की जगह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा (प्रतिस्पर्धा पर टिके समाज में ज्यादा मानसिक व शारीरिक हिंसा होती है, जिसका उदा० है अमेरिका है।) ऐसे समाज में समरसता की भावना का विकास होना मुश्किल होता है)

(ः) परिवहन व संचार क्षेत्र में हानि मूलतः नारों की खोज के रूप में हुई।
जैसे C. का परिणाम माना जा सकता है।
(ः) मुक्त प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार

(4) विभिन्न व्यक्तियों तथा वर्गों में आ० विषमता की वृद्धि।
(5) विशेषीकरण बढ़ने से मजदूरों में अलगाव की समस्या हो जाती है।
(6) व्यक्तियों की जरूरतों में लगातार वृद्धि होती है।

साधनों के कारण अधिक से अधिक भोग करने की मानसिकता पैदा होती है। ऐसा उपभोक्ता को कभी संतुष्ट ना होने वाला उपभोक्ता कहा जाता है। ऐरिक फ्राम की भाषा में कहे, तो ऐसा व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता, कि संतोष वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि अपनी सृजनात्मकता के साथ जीने में है।
पूँजी० ने यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इसी का चरम रूप W.W. की त्रासदी में देखा गया।

समाजवाद / विश्वासवादी S.

(+)ve हैं (1) राज्य का (क) कल्याणकारी स्वरूप
(2) विभिन्न वर्गों में कम विषमताएँ, समानता की स्थापना का प्रयास
(3) वस्तुओं का उतना ही उत्पादन, जितनी समाज को जरूरत है। अतः पर्यावरण पर अनावश्यक दबाव नहीं।
(4) अनावश्यक प्रतिस्पर्धा की जगह सामाजिक सहयोग पर बल ... [illegible]

(–) 1) अधिक योग्य व्यक्तियों में प्रेरणा व प्रोत्साहन की कमी, bcoz उनकी योग्यता का सम्पूर्ण लाभ उन्हें ना देकर समाज में बाँट दिया जाता है।

2) राज्य की शक्तियाँ बढ़ती हैं, जिससे व्यक्तिगत स्वाधीनता कम हो जाती है।

(3) व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा ना होने के कारण समाज में S&T व बाजार के स्तर पर वे नवाचार नहीं हो पाते। जो पूँजीवाद में अपने आप होते रहते हैं।

साम्यवाद

(–)ve (क्योंकि यह कहीं आया नहीं है, ∴ इसके व्यावहारिक पक्ष पर बात हो सकती है, साम्यवादी C. देशों में जो तानाशाही चल रही है। उसके व्यावहारिक पक्षों की बात की जा सकती है।)

(+)ve है → (1) प्रत्येक व्यक्ति रुचि के अनुसार कार्य करेगा, जो उसकी रचनात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में होगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही मिलेगा, जितनी उसकी जरूरत है। उसे धन संग्रह की अनावश्यक इच्छाओं से मुक्ति मिलेगा। तथा वह ज्यादा समय रचनात्मक कार्यों में दे सकेगा।

(3) राज्य की धारणा नहीं होगी, तो विभिन्न देशों में w. भी नहीं होंगे। w. के नहीं होने से हथियारों पर होने वाला निवेश खत्म होगा व उसे शिक्षा व स्वास्थ्य ...

4) धर्म का निषेध होने पर धार्मिक क्रिया व संघ विवाद भी खत्म होंगे। धर्मों के आधार पर होने वाला शोषण भी खत्म होगा। (जैसे - भारत में वर्ण व्यवस्था या विश्व में रंग भेद, लिंग भेद)

5) विवाह व परिवार का वह रूप खत्म होगा, जो शोषण पर है। केवल वही रूप बचेगा, जो प्रेम तथा सहयोग पर आधारित है।

(-)ve 1) हिंसा पर बल देना बुरा है, b/c कई ऐसे लोग भी मारे जाते हैं, शोषण व दमन के जिम्मेदार नहीं हैं।

2) किसी भी तानाशाही को उचित नहीं माना जा सकता।

(3) प्रेरणा व प्रोत्साहन की कमी

(4) नवाचारों के कमी आने का खतरा

(5) साम्यवाद का उद्देश्य अव्यवहारिक लगता है, b/c यह मनुष्य की कुछ प्रवृत्तियों जैसे - स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा व संचय का विरोध करता है

भारतीय समाजवाद गाँधीवाद + मार्क्सवाद का मिश्रण है।

- हिंसा का कोई स्थान नहीं — ×
- धर्म का निषेध नहीं — निषेध, भारत में ऐसा नहीं
- (यहाँ तक खुद नेहरू जी ने वैज्ञानिक धर्म की धारणा प्रस्तुत की)
- वर्ग सहयोग की बात स्वीकारी गयी है। | वर्ग संघर्ष की बात, जो India में नहीं

(यह सिद्धांत काफी हद तक गांधी की ट्रस्टीशिप के नजदीक है, bcoz इसमें ऊंचे वर्गों से उम्मीद की जाती है, कि वह स्वयं वंचित वर्ग का ध्यान रखेंगे।)

ग्रामीण विकास पर ज्यादा कम औद्योगि पर कम → India में दोनों को imp.

| — औद्योगिकरण पर ज्यादा बल, कृषि व ग्रामीण ढाँचे पर कम

भारतीय S. में दोनों प्रबल हैं।

- पंचवर्षीय योजनाओं का ढाँचा
- राज्य की शक्तियों को बढ़ना, जो महात्मा गाँधी के विचारों के विपरित था
- भूमि के पुर्नवितरण की कोशिश कैसे ही, जैसे रूस में हुई। हालाँकि यहाँ यह कोशिश ज्यादा सफल नहीं हुई।

Social Justice (सामाजिक न्याय)

Philosophy — वंचित वर्गों से संबंधित Act + latest development

लोकतांत्रिक
के द्वारा

सत्ता नीचे से ऊपर
विकेन्द्रीकरण

न्याय →
- गुण / सद्गुण (virtue)
- दृष्टिकोण
  - औपचारिक / प्रक्रियात्मक
  - तात्विक (Substantive)
- Method (विधि) → Natural Justice
- विभिन्न क्षेत्र
  - कानूनी न्याय (legal Justice)
  - वितरण मूलक न्याय (Distributive Justice)
    - सामाजिक न्याय
    - E. J.
    - P. J.

गुण / virtue → व्याख्या by प्लेटो, अरस्तू

→ जन्मजात नहीं, प्राप्त by कठोर अभ्यास

प्लेटो → सबसे imp virtue — न्याय

सबसे अच्छा न्याय वही करेगा जिसके व्यक्तित्व में

बेहतर समाज वही और जहाँ व्यक्ति न्यायपूर्ण — न्याय (इच्छा / वासना + विवेक + साहस) बनती का अनुपात ठीक

अरस्तू — तात्विक न्याय को लेकर कानूनी न्याय भी हो सकता है।

SC ने Natural Justice को 12-14

natural Justice
→ दोनों पक्षों की बात सुनें
→ के नियम जि

Natural Justice के

निश्चित कानूनों का पालन

1) - दोनों पक्षों को सुनवाई का अधिकार जरूर मिले

2) - न्यायधीश को किसी भी पक्ष से संबंधित नहीं होना चाहिए, अर्थात दोनों में से किसी भी पक्ष से उसके व्यक्तिगत हित नहीं जुड़े होने चाहिए।

3) - न्यायधीश को अपने दर्शन, अपने मूल्यों, अपने नैतिक संस्कारों तथा विचारधारा से भी तटस्थ होना चाहिए, ताकि उसका निर्णय किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हो।

4) - निर्णय मनमाने आधार पर नहीं, बल्कि ठोस, तार्किक तथा कानूनी आधार पर होना चाहिए। उसके साथ उन कारणों व आधारों की भी विस्तृत व्याख्या होनी चाहिए। जिन्होंने न्यायधीश को उस निर्णय पर पहुँचाया है।

5) निर्णय ~~से~~ द्वारा पीड़ित पक्ष को यह अधिकार होना चाहिए, कि वह समुचित मात्रा में निर्णय पर सवाल उठा सके व किसी वरिष्ठतर न्यायधीश द्वारा निर्णय पर पुनर्विचार हो सके।

कानूनी न्याय
↳ सर्वप्रथम by अरस्तू

- Retributive Justice → बदला लेना
(प्रतिकारी / प्रतिशोधात्मक न्याय)

- Remedial J. (उपचारात्मक न्याय)
- Rectificatory J. (सुधारात्मक न्याय)
- Communtative J.

अत्याचारी भी ही आज

कानूनी न्याय → that is संकीर्ण
- अदालत के द्वारा
- by न्यायधीश
- सभी समान

⇓

- समानता पूरी तरह से होनी चाहिए

दीवानी (Civil)
- दो व्यक्तियों का मसला टूटा
- सजा नहीं
- आर्थिक दण्ड

फौजदारी (Criminal)
- समाज के खिलाफ
- सजा होता है।

नया न्यायपूर्ण धारणा है।

~~वितरणमूलक न्याय~~

→ Distribution करते तीन चीजों का वितरण
- सामाजिक प्रतिष्ठा
- आर्थिक संसाधन
- राजनीतिक शक्तियाँ

दृष्टिकोण

औपचारिक → तात्विक

- NL (+)ve liberalism)
- स्वेच्छातंत्रवाद

इनके विचारक J. S. मिल व हुल्पा ने समर्थन किया

सकारात्मक उदारवाद
समतावाद

रॉल्स
न्याय
सिद्धांत

- व्यक्तियों की स्थितियों व उद्देश्यों के बीच दूरी बराबर

औपचारिक J.
- कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए।
- E-S-P क्षेत्र में भी ऐसे नियम होने चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति को बराबर समझते हो व किसी तरह का भेदभाव ना करते हो।

तात्विक न्याय

1) कानून सबके लिए बराबर हो, यह तो ठीक है, किन्तु यह भी देखना चाहिए, कि प्रत्येक व्यक्ति की कानून तक पहुँच बराबर हो यथा :- का० की जानकारी, अच्छे वकीलों की उपलब्धता etc.

2) यह भी देखा जाना चाहिए, कि अपराध करने वाला व्यक्ति किन विशिष्ट S-E या जैविक परिस्थितियों के अधीन था।

3) अगर ऐसी परिस्थितियाँ उसे मजबूर कर रही थी, तो ... ऐसे ... ... करती

जानी चाहिए।

वितरण मूलक — आर्थिक संसाधनों तथा सा० व रा० उपलब्धियों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि वंचित वर्गों के लोग भी इन लाभों को शामिल करने की प्रक्रिया में सचमुच बराबरी के स्तर पर आ सके। औपचारिक समानता पर्याप्त नहीं है। वंचित वर्गों के पक्ष में संरचनात्मक भेदभाव जरूरी है।

S. J. —

- उद्देश्य / स्थिति
- प्रक्रिया

उद्देश्य / स्थिति

— एक ऐसी स्थिति, जिसमें कानूनी तथा वितरण मूलक न्याय समाज के प्रत्येक सदस्य को न्यायपूर्ण तरीके से उपलब्ध हो।

— यथार्थ में नहीं

प्रक्रिया

— वे सभी साधन तथा उपाय, जो अन्यायपूर्ण सा० संरचना को बदलकर, समाज के विभिन्न समूहों को बराबरी पर लाने हेतु अपनाये जाते हैं।

— वंचित समूहों के पक्ष में की गई सम्पूर्ण सकारात्मक कार्य० (Affirmative Action) को इस अर्थ में सा० न्याय कहा जाता है। शिक्षा व रोजगार में आरक्षण, दलितों, अल्पसंख्यकों

से निःशुल्क चिकित्सा, बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा
जो भूम ह०, मनरेगा, स्वास्थ्य सुरक्षा इत्यादि
सभी उपाय इसमें शामिल हैं।

वंचित वर्ग / Deprived Section of Society

- शारीरिक रूप से
  - महिलायें
  - बच्चे
  - बूढ़े
  - विकलांग
  - Third Sex (तृतीय लिंगी)
- मानसिक
  - मनोरोगी
- सामाजिक
  - SC, ST
  - महिलायें
  - अल्पसंख्यक
  - LGBT (समलैंगिक समूह)
  - मैला ढोने वाले
- आर्थिक
  - गरीब (BPL)
  - असंगठित क्षेत्र में निम्न स्तर पर काम करने वाले
  - महिलायें
- राजनीतिक
  - महिलायें
  - SC, ST
  - अल्पसंख्यक (सिख, जैन)
  - Third Sex
  - उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (यहीं, SC, ST, अनुसूची)
- भौगोलिक
  - दुर्गम क्षेत्र
  - मध्यवर्ती क्षेत्र
  - द्वीपीय क्षेत्र
  - रेगिस्तानी क्षेत्र

welfare state
(उदारवादी state)

सर्वसत्ता 100% — 70 — 40% — 20
समानता 0% — 30 — 60% — 80%

उदारवादी — उदारवादी समाजवादी — समाजवादी लोकतांत्रिक — साम्यवादी

उदारवादी ⟷ समाजवादी

निष्कर्ष है० वर्तमान में उदा० व समाज० के मिश्रित रूप में

आर्थिक आरक्षण क्यों नहीं

- क्या criteria रखेंगे
- भिन्न आ० वर्ग में रखना निश्चित पैमाना नहीं
- corruption
- Individual difference

वितरण हेतु approach: मार्क्स, free market liberalism ((+)ve), (−)ve b/w मार्क्स, उदारवादी

Ques 1: वितरणमूलक न्याय से आप क्या समझते हैं, इसकी उपलब्धि के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं।

Ques 2: सा० न्याय क्या है। इसकी उपलब्धि के विभिन्न तरीके क्या हैं।

Ques 3: सामाजिक न्याय व आरक्षण के पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिये तथा अपनी राय भी बताइये।

Ques 4: भारतीय संविधान सा० न्याय के संबंध में क्या प्रावधान करता है, प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए।

- वि० मू० न्या० (O.J.), न्या का वह पक्ष है, जिसका संबंध अदालत की प्रक्रिया से नहीं, बल्कि समाज के आ० संसाधनों, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, अधिकारों, कर्तव्यों आदि के न्यायपूर्ण वितरण से है। यदि S. में सभी व्यक्तियों को न्यायोचित तरीके से इन लाभों में हिस्सा प्राप्त हो, तो कहा जा सकता है कि वह समाज वितरणमूलक न्या० की स्थिति में है।

इस संबंध में मूल समस्या है कि इन सामाजिक लाभों के वितरण की मूल कसौटी क्या होगी। विभिन्न राजनीतिक विचारकों व विचारधाराओं ने इस संबंध में अलग-2 कसौटियाँ निर्धारित की हैं।

1) इस Ans पर सबसे पहले व्यवस्थित विवेचन अरस्तू ने किया उसके अनुसार वितरण इस आधार पर होना चाहिए कि विभिन्न व्यक्तियों में कितने गुण हैं। स्वभाविक सी बात है, कि इस कसौटी में यह समस्या है, कि गुणों को परिभाषित कौन करेगा। किसी दृष्टिकोण से साहस गुण हो सकता है। तो किसी दूसरे " " ज्ञान

2) प्रमुख गुण माना जा सकता है। अरस्तू का Ans. है कि गुणों की परिभाषा परंपराओं तथा प्रथाओं से तय होती है। यह दृष्टि० अन्याय पैदा करने वाला है, क्योंकि तात्कालिक परम्पराएँ महिलाएँ तथा दासों को पूर्ण मनुष्य नहीं मानती थी। अरस्तू के इस सूत्र ने सा० अन्याय की जड़े और गहरी कर दी।

(ख) उदारवाद तथा नव-उदारवाद के समर्थक जैसे एडमस्मिथ, नॉजिक, हेयक (जिन्हे स्वेच्छातंत्रवादी भी कहते हैं।), कि स्पष्ट मान है, कि D. J. को सुनिश्चित करने वाली सबसे निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा सटीक व्यवस्था मुक्त बाजार प्रणाली है। F. M. में प्रत्येक व्यक्ति को कभी भी प्रविष्ट होने व बाहर निकलने का हक प्राप्त है। उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं की बाजार में उतनी ही माँग होती है। जितनी वह समाज हेतु उपयोगिता रखती है। इस D & S के अनुसार मूल्य का निर्धारण होता है। किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली आय या लाभ वस्तुतः उसके सा० योगदान का सटीक भौतिक मान है।

C. B. मैकफर्सन व टॉनी जैसे समतावादी विचारकों ने इस दृष्टिकोण को खारिज किया है। उनके अनुसार F. M. वस्तुतः F. M. नहीं है। वर्तमान में तकनीक व उत्पादन इतने महंगे हैं, कि कोई गरीब व्यक्ति उत्पादक होने की कोशिश नहीं कर सकता। ऐसे उसे पूँजीपतियों की मनमानी का शिकार होना पड़ता है। F. M. मजदूरों व गरीबों के अन्याय की व्यवस्था है। इसमें उन वस्तुओं का मूल्य नहीं है, जिनकी सांस्कृतिक उपयोगिता है, किन्तु जिनकी बाजार में माँग नहीं (उदा:- शास्त्रीय संगीत, ऐतिहासिक धरोहर इत्यादि)

(ग) मार्क्सवादियों का मानना है, कि सामाजिक लाभों का वितरण ना तो गुणों के आधार पर होना चाहिए नाहि योगदान के आधार पर, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों की जरूरतों या आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएँ अलग-2 होती हैं, तथा जीवन के विभिन्न चरणों में बदलती रहती हैं। एक न्यायपूर्ण समाज वही हो सकता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जरूरतों के अनुसार सुविधाएँ तथा लाभ मुहैया कराए। इसके लिए जरूरी है, कि निजि संपत्ति का पूर्ण निषेध हो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो तथा उत्पादन के समस्त साधन समाज के स्वामित्व में हो। ऐसी आदर्श अवस्था को ही साम्यवाद कहा जाता है।

एक वैचारिक कल्पना के तौर पर साम्यवाद का आदर्श भले ही श्रेष्ठ हो, किन्तु उसकी व्यवहारिकता संदिग्ध है। ...

मनोविज्ञान की दृष्टि से भी यह और प्रतीत होता है, पूर्ण स्वार्थ व प्रतिस्पर्धा से मनुष्य का पूरी तरह मुक्त हो जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

(घ) :- वर्तमान में विश्व के अधिकांश देश D. J. हेतु एक मध्यमार्ग पर चल रहे हैं, जो उदारवाद तथा मार्क्सवाद या पूँजीवाद तथा समाजवाद का समन्वय करता है। J. S. मिल, लास्की, मैकफर्सन, रॉल्स, जवाहर लाल नेहरू ने अपने-अपने तरीके से इसका समर्थन किया है। इसमें कुछ स्तर तक मुक्त बाजार को छूट भी जाती है, ताकि उद्यमशीलता हेतु मनोवैज्ञानिक प्रेरणा बनी रहे। साथ ही, कल्याणकारी राज्य विभिन्न उपायों द्वारा लगातार कोशिश करता है, कि विभिन्न वर्गों में अंतराल कम हो, तथा वंचित वर्गों को मुख्य धारा में शामिल होने के अधिकाधिक अवसर मिल सकें। भारतीय राज्य की नीतियाँ मोटे तौर पर इसी विचार का प्रतिनिधित्व करती हैं।

सामाजिक न्याय

क्या — तरीके

क्या :- S. J. एक आदर्श भी है, और एक प्रक्रिया भी। आदर्श के रूप में यह एक ऐसी स्थिति (सामाजिक) है, जिसमें समाज के विभिन्न समूहों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक संसाधनों, राजनीतिक शक्ति, अधिकारों व कर्तव्यों तथा प्रतिष्ठा में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी प्राप्त होती है। विभिन्न व्यक्तियों में अंतराल हो सकता [illegible]

होता, कि समाज ने उन्हें आगे बढ़ने के बराबर अवसर नहीं दिये वर्तमान में विश्व के एक भी समाज को इस आदर्श के समतुल्य नहीं माना जा सकता। 8. 8. न्याय का जो अर्थ प्रायः प्रयोग में आता है, वह उस प्रक्रिया से है, जो अन्यायपूर्ण समाज को न्यायपूर्ण S. बनाने हेतु प्रयोग में लायी जाती। इस प्रक्रिया के तहत कोशिश की जाती है, कि जो सामाजिक समूह सा० निर्योग्यताओं या अन्य भेदभावों के कारण मुख्य धारा से पिछड़ छूट गये हैं। उन्हें आरक्षण, वरीयता, मुफ्त शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि विशिष्ट सुविधायें देकर मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। विश्व के लगभग सभी विकसित व विकासशील C किसी न किसी मात्रा में सामाजिक न्याय के रास्ते पर चल रहे हैं। उदा:- हेतु USA मे 1950, 60 के दशक में अश्वेतों तथा महिलाओं के आंदोलन के बाद राजकीय स्तर पर ऐसी नीतियां अपनायी गयी। जो इन वंचित वर्गों को विशेष सुविधायें देती थी। इन सभी नीतियों के समूहों को USA मे (डायवर्सिटी नीति) कहा जाता है। भारत में बहुत सारे वंचित वर्गों के पक्ष मे ऐसे विशेष उपाय किये जा रहे हैं, जिनमें मुख्य भूमिका आरक्षण की है।

आरक्षण

(+)

- सा० समानता
- लोकतंत्र मजबूत

(−)

- vote bank की राजनीति
- ~~अनारक्षित~~
- जातिवाद

S.J. के पक्ष में आरक्षण

1) शांतिपूर्ण सा० व्यवस्था हेतु जरूरी है, कि विकास की प्रक्रिया में सभी बराबरी से शामिल हों, यदि कुछ वर्गों को लगातार अवसरों से दूर रखा जायेगा, तो कुछ समय के बाद धैर्य खत्म हो जायेगा। इसका परिणाम नक्सलवाद, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, लोकतंत्र में अविश्वास के रूप में सामने आ सकता है। ∴ समावेशी विकास समाज के अस्तित्व की शर्त है।

2) एक सच्चे लोकतंत्र का लक्षण है कि उसमें सभी ~~वर्गों~~/समूहों को आ० संसाधनों तथा राजनीतिक शक्ति में कम से कम उस अनुपात में हिस्सेदारी जरूर मिलनी चाहिए। जिस अनुपात में वे समाज का हिस्सा हैं। महिलाएँ दुनिया में 50% हैं, किन्तु कुल संपत्ति में हिस्सेदारी लगभग 1% है। ऐसी ही स्थिति अन्य वंचित वर्गों की भी है। अगर ऐसे भेदभाव चलते रहेंगे, तो लोकतंत्र का आदर्श कभी भी मूर्त नहीं हो सकेगा। (bcoz सच्चा लोकतंत्र केवल राजनीतिक नहीं होता उसमें आ० & S. लोकतंत्र भी शामिल होता है) (by नेहरू + अम्बेडकर)

③ एक अर्थ में S. J. क्षतिपूरक J. है। इसका अर्थ है, कि अतीत में जिन समूहों का वंचन हुआ उन्हीं की वर्तमान पीढ़ियाँ वंचन की स्थिति में हैं। दूसरी ओर अतीत में जिन समूहों को वंचित समूहों के हिस्से के अधिकार व लाभ मिले व पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक पूँजी (Cultural Capital) के रूप में उन समूहों को लाभ देते रहे। ∴ अगर वंचित वर्ग के लोग आज अयोग्य हैं, तो उनकी अयोग्यता का बड़ा कारण यह है, कि अतीत में उनके हिस्से के संसाधन दूसरों को योग्य बनाते रहे। इस भेदभाव की समाप्ति पक्षपातात्मक भेदभाव से हो भी जा सकती है।

4) J. एवं समानता जैसे आदर्श होने ही नहीं चाहिए दिखने भी चाहिए, कि उदा॰ हेतु यदि न्यायिक न्यायालय में कुछ न्यायाधीश महिला, SC, ST वर्गों से होंगे (योग्यता से समझौता किए बिना) तो इन वर्गों का न्याय प्रणाली पर अपने आप गहरा विश्वास पैदा होगा।

लिया है। कई विचारकों ने S. J. का विरोध किया है, जिनमें नव उदारवाद के समर्थक प्रमुख हैं। रॉबर्ट नॉजिक ने अपने अधिकारिता सिद्धांत (Entitlement theory) तथा F. A हेयक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "Law, legislation & Liberty: The mirage of S. J." में S. J. के सिद्धांत का पुरजोर विरोध किया है।

(1) J. का अर्थ यही है, कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार लाभ की प्राप्ति करे, S. J. साधने हेतु राज्य कुछ व्यक्तियों की आय छीनकर उन व्यक्तियों में बाँटता है, जो कम क्षमताएँ रखते हैं, या कम कुशल होते हैं। यह वस्तुतः कुछ व्यक्तियों की अधिकारिताओं को छीनने जैसा है।

(2) समाज के पास संसाधन सीमित मात्रा में हैं। अतः यह संभव नहीं है, कि सभी व्यक्तियों की सभी जरूरतें पूरी की जा सके। S. J. इस मूलभूत वास्तविकता को दरकिनार करता है, और एक वर्ग की आय छीनकर दूसरे वर्ग को बाँटता है।

(3) S. J. वस्तुतः उन व्यक्तियों को हासिल होता ही नहीं जिन्हें वह मिलना चाहिए। होता यह है, कि वंचित समूहों के भीतर एक अभिजात वर्ग (क्रीमीलेयर) इन सारे लाभों पर कब्जा कर लेती है, उदाः हेतु भारत में ~~कुछ 1700~~ कुल 1700 SC को मिलने वाले लाभों में से लगभग 90% लाभ

(4) सामाजिक न्या० के कारण ~~योग्य~~ व्यक्तियों के भीतर प्रेरणा का अभाव तथा उत्कृष्टता का हनन होता है। ऐसा होने से अंततः समाज का नुकसान ही होता है। ~~यदि अतीत मे कुछ व्यक्तियों~~

(5) यदि अतीत मे कुछ समूहों ने कुछ समूहों का शोषण किया, तो उसके ~~लिए उनकी~~ वर्तमान पीढ़ियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

(6) S. J. की प्रक्रिया में राज्य की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसके कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। स्वतंत्रता को नष्ट करके लायी गयी समानता का विशेष मूल्य नहीं है।

Social Justice, S. Welfare & Public policy in India

'सामाजिक न्याय' शब्द का अर्थ

सां० न्या० व कल्याण कोई नई संकल्पना नहीं है, और न ही इसकी कोई एक स्पष्ट परिभाषा देना संभव है। जैसे-2 मानव समाज बदलता है, वैसे-2 नई चुनौतियाँ उभरती हैं, और कल्याण के सिद्धांत के नए मापदण्ड विकसित होते हैं।

S. J. कई शताब्दी के मानव में उत्पन्न हुआ एक गतिशील सिद्धांत है।

ईश्वर तंत्र → राज्यतंत्र → लोकतंत्र – Democracy
⇓
न्याय का प्रतीक – संत – राजा
↓
Aristocracy (कुलीन तंत्र)
न्याय कौन – वंशवाद ⇓ – अराजकता

Aristotle
Distributive Justice ⇒ (according to need)

Equal should be treated equally and
Un " " " Un "

⇓
राज्य सीमा में बढ़ोतरी
⇓
क्रांति की हानि
↳ राज्य शोषण बनाये रखने उपायों पर भी ध्यान दें
⇓
IInd W. W.
↳ लोगों को हराना
⇓
Franklin रूजवेल्ट ⇒ सैनिक हेतु new scheme
⇓
Social security

रूजवेल्ट Joined
↳ सैनिकों को भत्ता लाभ —— पेंशन का

(Universal Decleration of Human Rights 1948)

⇓

भारत ने इसे अपनाया।

1950's - 60's S.J. का target → गरीबी, SC/ST

⇓

but now लैंगिक, ...

that shows गत्यात्मक concept — समय के अनुसार परिवर्तन

- सामाजिक J. का संबंध क्षेत्र, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, लिंग etc के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के अधिकार, गरिमा व आवाज उठाते है।

- S.J. समाज में हाशिए पर धकेले गये लोगों (Marginalized), दलितों व असुरक्षित समूहों को E-S-P सशक्तीकरण सुनिश्चित करता है।

S.J. के संदर्भ में न्यायिक धारणा

D.S. Nakara v/s UOI (...)

[illegible] v/s [illegible] (2000) → ... S.J. की भिन्न व्याख्या।

A.K Gupta v/s VP [illegible]

1) सामाजिक न्याय विधि को बनाए रखने में न्यायालयों को सक्षम बनाता है —

- आर्थिक असमानताओं को दूर करने हेतु

- वंचित व्यक्तियों को जीने के उचित मानक प्रदान करने के लिए — Right to Dignity

- समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए।

S. J. के मूल तत्व

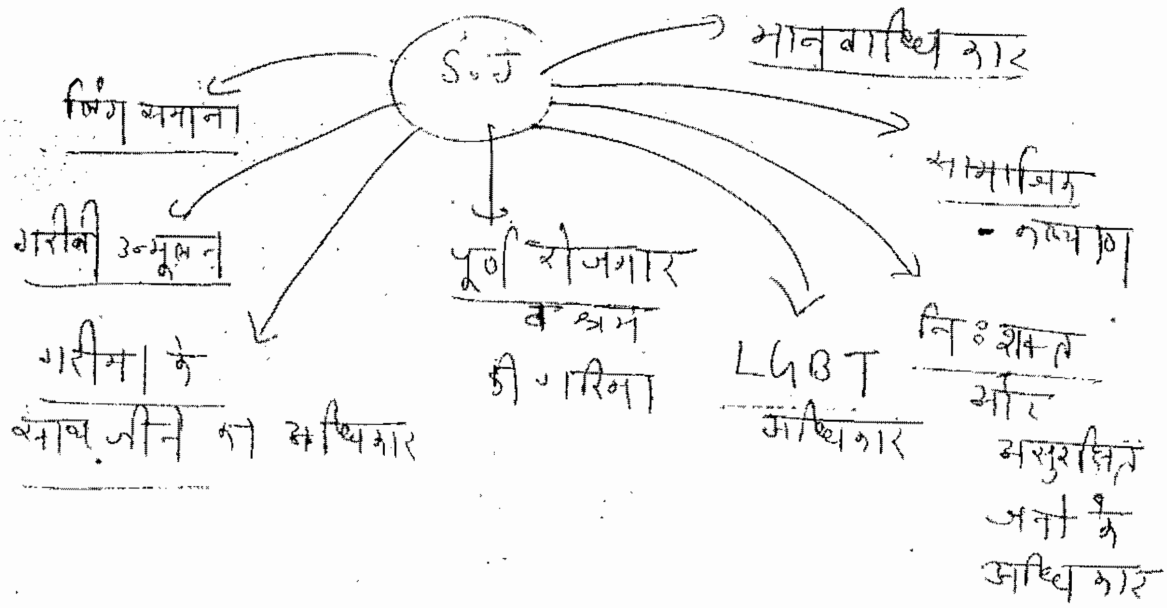

सामाजिक न्याय से संबंधित कुछ imp. प्रश्न

1) सामाजिक न्याय में क्या निहित किया जाता है
- संसाधनों तक पहुँच
- क्षमताओं के विकास हेतु सकारात्मक भेदभाव की नीति के अंतर्गत

अवसरों की उपलब्धता

2) न्याय से लाभान्वित लोग कौन होंगे?
- समाज के असुरक्षित, दुर्बल तथा हाशिये पर धकेले गये लोग

3) [illegible]
P - S - E (शारीरिक)

4) न्याय का स्वरूप क्या होगा
Bottom - UP (निचले स्तर से ऊपर)

(5) वितरण का कार्य कौन करेगा ?

1) NGO
2) सरकारी एजेंसीयाँ
3) SHG's
4) Micro Finance Institution

(6) न्यायपूर्ण वितरण के लिए सफलता या असफलता का आकलन कैसे किया जाएगा ?

एक निश्चित समय सीमा में सफलता या असफलता निर्धारित नहीं की जा सकती, लेकिन निम्नलिखित तात्कालिक किया जा सकते हैं।

- Social Audit
- Gender Audit

भारत में S. J. की आवश्यकता [illegible]

(1) सांस्कृतिक व धार्मिक कारण (वर्ण व्यवस्था आदि)

(2) ऐतिहासिक कारण (ब्रिटिश काल के समय)

(3) सर्वहारा के समान भारतीय समाज

(4) भारत के संविधान का निर्माण

(5) उत्तर-वैश्वीकरण युग में भारतीय समाज की समस्याएं (S-E कारण)

Social Justice

[illegible]

Economic Justice

Political Justice

भारत में S. J. को समझने में सहायक सीखने योग्य

(भारत में असुरक्षित / हाशिए पर तथा शोषित समूह / वर्ग कौन हैं?)

सामाजिक रूप से वंचित समूह
- ST
- SC
- Minorities
- OBC

सा० रूप से शोषित समूह
- Women Children
- विकलांग
- अन्य सामाजिक रूप से बहिष्कृत
- वृद्धजन
- Unorganised Sector / Labourers

सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूह

1) किशोर अपराधी
2) भिखारी
3) महिला सेक्स वर्कर
4) HIV / एड्स रोगी
5) गली बच्चे
6) मादक पदार्थों का सेवन करने वाले

→ जो समाज से पूरी तरह Deviant हो चुके हैं।

भारत को कल्याणकारी राज्य क्यों कहा जाता है।
↳ इसमें वर्ग प्रावधान शामिल हैं / असुरक्षित वर्गों के कल्याण की व्यापक

1) NSAP (National Social Assistance Prog.) — इंदिरा गांधी पेंशन योजना
2) मनरेगा
3) इंदिरा आवास योजना
4) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PAGY)

- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
- समावेशी समूहों को प्रोत्साहन
- सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
- संवैधानिक तथा विधायी ढांचा ⇒ (DPSP)
- सकारात्मक कार्यवाई
- फेलोशिप और छात्रवृत्ति
- सामुदायिक विकास → Tribal — भारत सरकार की योजना T.S.P (ST उपयोजना)
- सा० और राजनीतिक असमानता का निवारण

⇒ DPSP
↳ A - 38, 39, 41, 42, 46, 47

असुरक्षित वर्गों/समूहों के कल्याण हेतु भारत में की गई पहल है —

(क) प्रधानमंत्री A. G. Y (2009-10)
(ख) असंगठित क्षेत्र कामगार सा० सुरक्षा अधि० 2008 और रा० सा० सुरक्षा निधि

- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY)
- गैर-अधिसूचित, घुमन्तू (Nomadic) और अर्द्ध घुमन्तू (Denotified) जनजातीय समुदाय और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के विकास पर बल।
- निःशक्तजनों, हाथ से मैला ढोने वाले, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों एवं वृद्धजनों के लिए विशेष योजना का क्रियान्वयन

निशक्त ⇒ Super speciality aples T

(ङ) (PAGY) :- started → 09-10

जिसके तहत 44,000 गाँव चिन्हित किये गये। जहाँ पर SC's की pop 50% से अधिक थी, के सर्वांगीण विकास की बात

(शौचालय, school की सम्पर्क, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सुदृढ़ करना)

(च) असंगठित :-

→ RSBY (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) के अंतर्गत सब unorganised क्षेत्र के कामगारों को शामिल करना।

ग) IGMSY → 53 शहरों में

↳ Pregnant women + Lactating को 4,000 रु का अनुदान देना

↳ ग्रामीण क्षेत्रों की वो महिलाएँ जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

→ आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों

↳ (दंगों/संघर्ष के कारण)

भारत में असुरक्षित वर्गों/समूहों हेतु S.J. की स्थापना के लिए 12वीं 5yp में निर्धारित लक्ष्य

- 13 अग्रणी विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना

(12th 5yp का main focus on Nutrition)

- 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में MSDP
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई राष्ट्रीय नीति
- SC/ST के विकास हेतु नरेन्द्र जाधव समिति की संस्तुतियों को लागू करना।

– 12th FYP के अंत तक IMR को घटाकर 25 व MMR को 1 प्रति 1000 जीवित जन्म करना

0 – 6 age group में sex ratio को बढ़ाकर 950 करना

Facts —— Law/Legislation ——→ Welfare

Census – 2011 | 2001

⇒ भारत की pop का कुल 70% महि० + बच्चे हैं।

⇒ लिंगानुपात ⇒ 940 ——— 933

⇒ 0-6 ⇒ 914 ——— 927

⇒ W. Literacy rate ⇒ 65.46

M " " ⇒ 82.14%

T " " ⇒ 74.04%

⇒ IMR ⇒ 47

⇒ MMR ⇒ 212

⇒ 5 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं में M.R. ⇒ 64/1000

Reason for low sex ratio
- under weight
- mother suffers from nutrition
- Nutrition level

∴ 12th 5 yp में aim → Child nutrition level को तेजी से बढ़ाना

MMR ⇒ 11th में target ⇒ 100
- no gain bcoz of nutrition ↓

भारत में कुल 30 लाख sex worker हैं, जिनमें से 36% 18 वर्ष से कम आयु की हैं।

Child Nutrition

- प्राथमिकता
  - Adolescent (11-18) girls
  - Infant girls (नवजात)
- Child प्रोटेक्शन (बाल संरक्षण)

भारत में असुरक्षित महिलाएँ तथा महिला समूह

- बलात्कार पीड़िता
- भूमिहीन महिला
- HIV पीड़ित
- बंधुआ महिला श्रमिक
- निःशक्त महिला
- विस्थापित महिला
- शरणार्थी महिला
- अल्पसंख्यक महिला
- किशोरी लड़कियाँ (11–18 वर्ष)

Double Vulnerable

(1.) Dalit + Bonded labourers

(नई रोशनी) ← (2.) Minorities + Disabled

(3.) illiterate + Construction site

⇒ भारत में योजना प्रक्रिया तथा महिला सशक्तीकरण
भारत सरकार की योजना प्रक्रिया के विकासात्मक रूप रेखा में महिलाओं की imp. भूमिका स्वीकार करते हुए, विशुद्ध रूप से एक कल्याणोन्मुखी दृष्टिकोण अब सशक्तीकरण के रूप में परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है।

⇒ छठी व 7वीं 5YP में मुख्यतः W. के स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार पर बल दिया गया, जबकि 8th के दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव देखा गया। जिसमें महिलाओं के सशक्तीकरण को स्वीकार किया गया, और उसे एक विशिष्ट कार्य नीति समझा गया। 9वीं Y का दृष्टिकोण गरीबी में रह रही महिलाओं तक पहुँचना और उन्हें स्वयं सेवी समूहों (SHG) जैसी पहलों के माध्यम से स्वयं अपनी मदद करने का मार्ग निर्देशन प्रदान किया गया।

⇒ 10वीं Y. में पहली बार मानवीय विकास के प्रमुख संकेतकों को स्थापित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये। जैसे साक्षरता, मजदूरी की दरों में लैंगिक अंतराल कम करना है तथा MMR में कमी लाना।

→ 11वीं 5yp समावेशी विकास के प्रति लक्षित थी, और स्त्री लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 12वीं 5yp में किशोरियों को सामर्थ्यवान बनाने हेतु 'सबला' योजना, अनैतिक व्यापार को रोकने हेतु उज्जवला तथा घटते हुए लैंगिक अनुपात के मुद्दे से निपटने हेतु 'धन लक्ष्मी' शामिल है।

now 11th + 12th

Social upliftment → सशक्त → Skill Development ⇒ (NSDC निगम)
(उत्थान)

महिला सशक्तीकरण की राह में बाधाएं

- लिंग पूर्वाग्रह तथा भेदभाव की विचारधारा की गहरी जड़ें।
- स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा रोजगार तक पर्याप्त पहुंच का अभाव
- लिंग आधारित हिंसा
- Gender Inequality Index of India

2010 में जोड़ा गया

मान 2011 → 0.617 (रैंकिंग 129/149)

GII Ind
- प्रजनन स्वास्थ्य (Reproductive Health) (प्रसव स्वास्थ्य हेतु कैसी सुविधा)
- Empowerment (का स्तर क्या है)
- Labour Market (महिलाओं का कितना + किस स्तर का %)

महिलाओं हेतु भारत में imp विधि, विधान एवं संवैधानिक प्रावधान

संवैधानिक प्रावधान :-

A : 15(1), 15(3), 42, 47, 51A(e), 243D(3),

243D(4)

कानूनी प्रावधान —

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध धारा
(Sexual Harassment)

Rape — 376, 509, 354, 292, 294 → OBSCENITY (अश्लीलता)

H R संरक्षण Act, 1993

⇒ राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001

(1) जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति, विकास व सशक्तीकरण।

(2) अधिक संवेदी न्यायिक कानूनी प्रणालियाँ, जो कि W की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।

(3) समुदाय आधारित संगठनों के साथ भागीदारी

(4) विकास प्रक्रिया में जेंडर परिप्रेक्ष्य की मुख्य धारा

महिलाओं के संरक्षण हेतु Imp. Act + विधेयक

— विशाखा दिशा निर्देश :-

1997 Case वि. vs राज

Gender/Sex Adult Education

- कार्यस्थलों तथा अन्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम करना और ऐसे विवादों के समाधान तथा कानूनी कार्यवाही के लिए उचित कदम उठाना नियोक्ता अथवा किसी जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य होगा।

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या निषेध करने वाले नियमों की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इनका परिपालन वितरण भी किया जाना चाहिए तथा इनमें यौन उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ दण्ड का प्रावधान भी होना चाहिए।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण Act, 2005

(DWA, 2005)

- 26 Oct, 2006 को यह Act लागू किया गया। जिसके तहत घरेलू हिंसा की शिकार महिला को चिकित्सा सुविधा के रूप में तत्काल सहायता प्रदान करना और साथ ही उसके बच्चों को अस्थायी रूप से महिला के सुपुर्द करना

- गर्भधारण और प्रसव पूर्व तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) Act, 1994 (P.C. PNDT Act, 1994)

(1) प्रसव पूर्व नैदानिक तक० का प्रयोग असामान्य परिस्थितियों में ही करना चाहिए, ना कि लिंग निर्धारण हेतु

(2) प्रसव पूर्व नैदानिक प्रक्रिया को संपन्न करने वाला व्यक्ति भ्रूण की लिंग संबंधी जानकारी महिला या उसके रिश्तेदारों को किसी भी रूप में नहीं देगा।

Cognizable offence (संज्ञेय) → (बिना कोर्ट के वारण्ट के भी FIR)

MTP Act, 1971 — माँ की जान को खतरा हो तो abortion allowed ⇓ misuse ⇓ ∴ PCPNDT Act

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, प्रतिषेध व निवारण) Act, 2013

(1) 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी संस्थान में एक अंदरूनी शिकायत सेल जरूर होना चाहिए।

(2) किसी भी शिकायत का 90 दिन के भीतर निवारण होना

- महिलाओं का अशिष्ट निरूपण (निषेध) संशोधन विधेयक, 2012

[Immoral representation of women (Prohibition) Amendment Bill, 2012

- मूल कानून (1986) है —
  - किसी भी प्रकार के विज्ञापन, प्रकाशन या लिखित रूप से स्त्री का अशिष्ट निरूपण नहीं होना चाहिए।

new Bill (संशोधित) है →

↳ पुराने बिल में इन्हें सम्मिलित किया है,

↳ MMS, e-Media, Satellite operated, Electronic Media

महिलाओं के कल्याण हेतु 12वीं 5 y का रुझान।

- आर्थिक सशक्तीकरण
- S व भौतिक अवसंरचना।
- कानूनों का सक्षम बनाना
- कमजोर महिलाओं की सभी श्रेणियों का समावेश
- जेण्डर बजटिंग

महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु एजेंसी एवं संस्थाएं

- राष्ट्रीय महिला आयोग
  ↳ 1992

रा० म० स० मिशन

Started in 8 मार्च, 2010

- इस मिशन के अंतर्गत भारत सर० के सभी मंत्रालय महिलाओं की शिक्षा, गरीबी उन्मूलन व सशक्तीकरण को ध्यान में रखकर अपनी नीतियाँ निर्धारित करेंगे।

↳ Tribal A M. ने जनजातिय क्षेत्रों की महिलाओं के अधिकारों की बात की।

- राष्ट्रीय महिला आयोग
- " " कोष

भारत में बाल असुरक्षा

- घटता शिशु ~~बाल~~ लिंगानुपात (0-6) ⇒ हरियाणा (774)
  हरि - 830, पंजाब - 846
- बाल-कुपोषण का उच्च स्तर
  (22% नवजात शिशुओं का वजन कम होता है।)
- बच्चों (0-6 वर्ष) में रक्ताल्पता की बहुलता
- बालिकाओं की भारी असुरक्षा (शिशु हत्या, भ्रूण हत्या)

संवैधानिक R.

A - 15(3), 21(A), 24, 39(F), 45, 51 A(k), 243 G

विधि, अधि० एवं विधेय० है —

- बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का

- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण Act, 2012
- बाल अपराध न्याय Act, 1986 (बाल अपराध न्याय Act 2000 द्वारा प्रतिस्थापित)

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण Act, 2012

- 18 वर्ष से कम किसी भी बच्चे का यौन शोषण या यौन उत्पीड़न वर्जित है। व इसे एक जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जायेगा। तथा यौन उत्पीड़न निकृष्ट यौन उत्पीड़न आदि में दोष मुक्त साबित करने का भार दोषी पर स्वयं होगा।
- इस अधि० की निगरानी रखेगा → राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) (NCPCR)
- पुलिस थानों में एक विशेष बाल अपराध इकाई स्थापित की जायेगी।
- 24 घन्टे के अंदर बच्चे की चिकित्सीय जाँच होनी चाहिए

Note

जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट व J J बोर्ड की कार्य प्रणाली में क्या फर्क है?

Imp. ICDS

कल्याणकारी योजना

- बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2005
- ICDS
- राजीव गाँधी N शिशुसदन योजना।
- राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा योजना (...)

- किशोर बालिकाओं हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPAG)
- समेकित बाल संरक्षण योजना
(Integrated Child Protection Scheme)
चार घटक हैं—
(1) बाल अस्तित्व
(2) बाल विकास
(3) बाल संरक्षण
(4) बाल भागीदारी

बाल कल्याण हेतु एजेंसियाँ एवं संस्थाएँ

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
- चाइल्ड बजटिंग
- रा० जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (NIPCCID)
- भारतीय बाल कल्याण परिषद
- किशोर न्याय बोर्ड
- Childline — 1098
  - This is a helpline
  - by SHG → Child line foundation चला रही है।

Ans :→ S. J. को एक प्रगतिशील सिद्धांत क्यों कहा जाता है, उदाहरण सहित प्रस्तुत करें।

Ans :→ 12वीं 5YP किस प्रकार महिलाओं तथा बच्चों के बहुआयामी विकास हेतु imp सिद्ध होगी ?

Ans :→ भारत के उन imp अधिनियमों को रेखांकित कीजिए, जो महिला संरक्षण के लिए हैं ?

Ans :→ महिला संरक्षण का विकेन्द्रीकरण कैसे संभावित है ? उदाहरण सहित प्रस्तुत करें।

Ans :→ किशोर J. B. की कार्यप्रणालियों में क्या परिवर्तन लाये जाने चाहिए।

(Factual) :- 2011

SC ⇒ 16.6% ;

ST ⇒ 8.7%

आज भी 3.5 करोड़ से अधिक हाथ से मैला ढोने वाले हैं।
HDI के सभी मापदंडों की दृष्टि से शेष आबादी की तुलना में ये समूह अत्यंत कमजोर हैं।

Tribes → Himalayan, Chota Nagpur → अंग्रेज → no man's land → Criminal tribe

SC   ST   OBC
जाति आधार → गैर आधार पर आरक्षण
⇓
विवाद
⇓
मंडल आयोग

SC तथा ST :-

प्रस्तावना :-

SC's तथा ST's के सदस्य देश में निम्नतम वर्गों से हैं, तथा उनके साथ सर्वाधिक भेदभाव किया जाता है। भेदभाव प्रायः S-E शोषण, नागरिक अधिकारों की मनाही, सा० बहिष्कार और यहाँ तक की उनके विरुद्ध हिंसा के रूप में होता है। जो कभी-कभी सामूहिक हत्याओं, बलात्कार, बस्तियाँ जलाने आदि का रूप ले लेता है।

ST/SC (Social protection)

- संरक्षण
- सुरक्षात्मक भेदभाव
- विकासपरक योजनाएँ

(1) संरक्षण :-

विधि/कानून के अनुसार संरक्षण ⇒ 1) नागरिक अधिकार संरक्षण अधि०, 1955
2) SC तथा ST (अत्याचार निवारण) Act, 1989

(2) सुरक्षात्मक भेदभाव :- सार्वजनिक सेवाओं प्रतिनिधिक निकायों व शिक्षा संस्थानों में आरक्षण प्राव० लागू करना।

(3) विकासपरक योजनाएँ :- SC's एवं ST's की आर्थिक स्थितियाँ व सा०-स्थितियाँ अन्य समुदाय की अपेक्षाकृत बेहद निम्नतम स्तर पर रहती हैं, तथा इस अंतराल को पाटने हेतु विभिन्न प्रकार की विकास परक योजनाओं का लागू होना। इस हेतु SC उप योजना (SC SP)

TSP (Tribe Sub plan)

SC का संरक्षण

संवैधानिक प्रावधान
A - 17, 15, 46, 338, 341, 332, 243 D, 243 T

प्रमुख Act
(PCR Act) नागरिक अधिकार संरक्षण Act, 1955
- SC & ST (अत्याचार निवारण) Act, 198[illegible]

⇒ PCR Act, 1955
↳ इस Act के तहत अस्पृश्यता के आधार पर किये गये अपराध परिभाषित हैं। और उन अपराधों के लिए दण्ड के प्राव० विशेष अदालतें, विशेष थाने हैं।

↳ इस Act को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता केन्द्र करता है।

⇒ SC & ST (अत्या० निवा०) Act, 1989
→ इस Act को कार्यान्वित करने हेतु केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को प्राप्त होती है, तथा इसके प्रमुख प्रावधान हैं :-
(1) विशेष अदालतें
(2) [illegible] अधिकार
(3) विशेष लोक अभियोजन
(4) राज्य तथा जिला स्तरीय सतर्कता व मॉनिटरिंग समिति
(5) विशेष पुलिस थाने

SC के कल्याण हेतु प्रमुख प्रावधान

- SC SP (1978) है
↓
एक फण्ड का गठन
↓
तीन में वर्गीकृत

राज्य एवं केन्द्रीय — विशेष केन्द्रीय सहायता — राज्यों में SC विकास निगम

संगठनों से suggestion → National Advisory Council → मंत्रालयों के रिपोर्ट → कैबिनेट → पास

SCSP में नरेन्द्र जाधव समिति

→ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना :-
- 44,000 ग्राम
- 50% से अधिक SC's pop
- समग्र विकास

→ बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना
- girls hostel हेतु 100% का अनुदान
- Boys " " 50 " "

→ राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना
- SC के छात्र जो Mphil या PHD कर रहे हैं, उन्हें फेलोशिप देना।
- 1 अप्रैल, 2010 में प्रारंभ

→ राष्ट्रीय SC वित्त एवं विकास निगम (NSCFDC)
- 1989 में कंपनी अधि०, 1956 के अंतर्गत स्थापित
- मुख्य उद्देश्य :- रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना for (1) उद्यमशीलता (2) Skill
- क्रियान्वयन by → RRB (रीजनल रूरल बैंक) → नाबार्ड

Qus :- भारत में SC समुदाय के आ० विकास को सुदृढ़ करने हेतु किस प्रकार के प्रशासनिक उपाय उठाये जाने चाहिए।

Depressed Class (महादलित)

⇒ भारत में हाथ से मैला ढोने वालों के कल्याणकारी

हाल ही

योजनाएँ / संस्थाएँ :-

- हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्व नियोजन योजना, 2007
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग तथा रा० सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC)

प्रमुख Act :-

- हाथ से मैला ढोने वालों का नियोजन तथा शुष्क शौचालय का निर्माण (निषेध) Act, 1993
- हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 :-

(1) यह विधेयक मैला ढोने वालों के पुनर्वास एवं वैकल्पिक रोजगार की व्याख्या करता है।

(2) स्थानीय संस्था, प्राधिकरण व जिला अधिकारी इसके क्रियान्वयन हेतु प्राधिकृत होंगे।

(3) विधेयक के अंतर्गत अस्वच्छ शौचालयों (शुष्क) का सर्वेक्षण स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी मशीनरी, छावनी बोर्ड व रेलवे बोर्ड जैसी संस्थाएँ करेंगी।

(4) इनके पुनर्वास हेतु नोडल एजेंसी → NSKFDC

NGO's
सफाई कर्मचारी आंदोलन
बिल निर्माण में imp भूमिका

Que New बिल of Manual Scavengers के S-E परिणाम क्या हो सकते हैं, उदाहरण सहित प्रस्तुत करें।

S → Inclusive society

E → Skilled Human resource.

ST

संवैधानिक प्रावधान → Imp. अधि०/संस्थाएँ :-

A-342, 366(25), 338A, 244, 244(1), 244(2), 275(1), 339, 46

- ST तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) Act, 2006
- पेसा, 1996
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

वन अधिकार Act, 2006 :-

- यह कानून 1 Jan, 2008 को अपने सभी प्राव० के साथ लागू हुआ

1) यह Act वन भूमि स्वामियों, ग्राम सभाओं को यह अधिकार देता है, कि वह अपने वनों को संरक्षित कर सके।

2) लघु वन उत्पादों पर पूर्ण अधिकार
   तेंदू पत्ता, बाँस, वन औषधि

3) ग्राम सभा के अधीन गठित समितियाँ सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा व संरक्षण की योजना बनायेगी।

पेसा, 1996 :-

1991 – Bhuria कमिटी का गठन
said → ST's का उनके क्षेत्रों से पलायन

✓ अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायती राज का विस्तार
✓ देश के 9 राज्यों में

प्रमुख प्राव :-

(1) प्रत्येक गाँव में एक ग्रामसभा होगी, जो अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा, पहचान एवं सामुदायिक संसाधनों को संरक्षण करेगी।

(2) पेसा कानून के तहत ST's को पंचायतों में अध्यक्षों की सभी सीटों पर आरक्षण होगा, तथा लघु वन उत्पाद पर सभी निर्णय ग्राम सभा का ही होगा।

समाथा दिशानिर्देश (1997) →

औद्यो० की NGO

- खनन हेतु सबसे पहले ग्राम सभा से approval ले
- मुनाफे का 20% – Tribes welfare

Ques → पेसा, 96 तथा वन अधि० Act, 2006 में किस प्रकार नीतिगत परिवर्तन लाये जाने चाहिए, ताकि इन अधि० का मूल aim पूर्ण रूप से होते हुए दिखे।

2nd ARC (7th report) ने पेसा, 1996 में सुधार हेतु

1) पहले पुनर्वास फिर विकास

2) P-96 तथा FRA पूर्ण रूप से बाकि विकासपरक योजनाओं के तहत होना चाहिए।

- → land Acquisition Act
- → National Mineral policy

ST संबंधी प्रमुख योजना

- TSP
- लघु वनोत्पाद संघों हेतु अनुदान।
- आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना।
- NSTFDC
- आदिम जनजातीय समूहों के लिए विकास योजना है

⇓

(Primitive Tribal group)

⇒ India में 75 PTG हैं।

अवस्थान → संरक्षण, अस्तित्व, विकास

ITDA (एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी) :-

↳ वर्तमान 250+से ITDA

(OBC's)

मुसलमान, मण्डल आ० के acc. 3473 जातियाँ भारत में OBC के अंतर्गत आती हैं।

— मंडल आयोग के 52% तथा NSSO (2004-08) के अनुसार 42% आबादी OBC's से आती है।

— 2001 मुसलमानों में 59.1% साक्षरता
  " महिलाओं 50.1% "

विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं 4 OBC + Minorities

(1) छात्रवृत्ति योजनाएँ
(2) PM नवीन 15 सूत्री कार्य०
(3) नई रोशनी — अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना
(4) सीखों व कमाओ => कौशल विकास
(5) MDS

(नई रोशनी) :- इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों के विषय में जानकारी, साधन एवं उनसे पारस्परिक क्रियाओं की तकनीक प्रदान कर उन्हें आत्म निर्भर बनाना है।

Multisectoral D S :-

90 अल्पसंख्यक जिलों में चल रही योजना है, जिसके अंतर्गत आय उत्पन्न करने वाले अवसर एवं शिक्षा, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के मकान, सड़क व पेयजल से संबंधित हैं।

भारत में निःशक्त जनों तथा कामगारों के लिए गठित तंत्र विधि, संस्थाएं, निकाय एवं कल्याणकारी योजनाएं

आर्वेद आश्रिती
for विकलांग people
(AMU)

कुछ imp facts

acc to 2001 Census
विकलांग ⇒ 2.1% of T. pop.
75% (Rural Area)

2001 में पहली (census) बार विकलांगता की श्रेणी सम्मिलित

93 lakh woman disabled

bcoz → कई अंत. कन्वेंशन
- कई डेमोक्रेटिक (विवाको मिले) 2003 फ्रेमवर्क
⇓
Asia & Pacific region में जितने भी वि. लोग हैं, उनके अधिकार हेतु
- Inclusive society बनाने हेतु Govt आगे आये
- Barrier free society
- सरकार Rights Based approach अपनाये।
  - नागरिक अधिकार
  - Human right

- विकलांग साक्षर ⇒ 45%
- रोजगार ⇒ 34%

acc to 2011
विकलांगों की 8 श्रेणियां
- दृष्टि वि.
- वाक् "
- मानसिक
- बहु - विक.
- श्रवण वि.
- चलन "
- मानसिक रो
- कोई अन्य विकलांगता

→ विवाको के तहत ही 2011 में 8 श्रेणियां

3 new category
- मानसिक वि.
- " रोग
- कोई अन्य वि.

1st
1981 में राष्ट्रीय जनगणना
1981 + 2001 जन. में शामिल

why vulnerable
bcoz
अधिकारों का लोप

भारत में विकलांग व्यक्तियों के जोखिम :-

(1) वैधानिक अधिकारों के प्रति अनभिज्ञता

(2) सामाजिक बहिष्कार

(3) पुनर्वास सुविधाओं का अभाव

(4) स्वास्थ्य ,, ,, ,,

(5) साक्षरता का निम्न स्तर

(6) पहुँच का अभाव

(7) यौन उत्पीड़न

(8) उपेक्षा, हिंसा तथा दुर्व्यवहार

विकलांगों के कल्याण व सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान और विधि विधान

- संवैधानिक अधिकार :-

A - 14, 21, 41, 39-A, 46, 47, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची
(243(G) पंचायत) (243(W) म्युनिसिपलटीज)

- प्रमुख Act :-

• निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) Act, 1995 :- (PWD Act, 1995)

why in 1995 because — 1991 में UN Convention on the rights of disabled था गया था।

[illegible]
भारत में disabilities defined by this Act

प्रस्तावना :-

निःशक्त व्यक्तियों की परिभाषा :-

(i) निःशक्त व्यक्ति से अभिप्राय है, ऐसा एक व्यक्ति, जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी निःशक्तता से 40% कम ग्रस्त ना हो। तथा निःशक्तता से तात्पर्य है —.

(A) नेत्रहीनता (B) कम दृष्टि (C) कुष्ठ रोग मुक्त (Leprosy free) ⇒

ऐसे व्यक्ति से अर्थ है, जो कु० रो० से तो मुक्त हो गया है, किन्तु हाथों या पैरों में संवेदना की कमी व आंशिक घात से ग्रस्त है, किन्तु प्रकट विरूपता से ग्रस्त नहीं है।

(D) श्रवण शक्ति का कम होना (E) चलन निशक्तता

(F) मानसिक मंदता (G) किसी मानसिक रोग से ग्रस्त

change

b/c3

⇒ विकलांग हेतु पर्याप्त नहीं

⇒ आरक्षण पर्याप्त नहीं

<u>विशेषताएँ :</u>

- नि० व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी तथा समानता संबंधी स्वीकृत उद्घोषणा को प्रभावी बनाने हेतु निशक्त व्यक्तियों के लिए यह Act बनाया गया है।
- यह Act Centre Govt., राज्य Govt. तथा स्थानीय प्राधिकरणों पर विकलांग व्यक्तियों की निशक्तता की रोक थाम, शीघ्र बचाव, शिक्षा, रोजगार सहायता, उपकरणों के प्रावधान, सार्वजनिक स्थानों पर उनकी पहुंच को सुगम बनाने हेतु निश्चित दायित्व सौंपता है।
- इस Act में विकलांग जनों के बारे में अनुसंधान, जनशक्ति विकास, सा० सुरक्षा, शिकायतों के निवारण तंत्र, भर्तियों तथा निधियों के उपयोग शामिल है। Centre में एक केन्द्रीय समन्वय समिति Act में दिये गये प्रावधान की जांच करता है, तथा केन्द्रीय कार्यपालक समिति, केन्द्रीय समन्वय समिति के आदेशों को लागू करती है।
- इस Act के तहत सरकारी शैक्षणिक संस्थानों और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में 3% आरक्षण का प्रावधान करता है।

(Care-based Policy)

बच्चे बोलते नहीं (टेरके) → (4) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु एक – राष्ट्रीय न्यास Act, 1999

(National trust Act, 1999):-

प्रमुख विशेषताएँ :-

(1) संरक्षकों की नियुक्ति (no parents & Guardian)
↳ (जिलाधिकारी संरक्षक की नियुक्ति

(2) स्थानीय स्तरों की समितियों का गठन :- (↳ work → free shelter)

(3) विकलांग व्यक्तियों हेतु अभिभावकों व न्यासी की नियुक्ति हेतु कार्य प्रक्रिया तैयार करना।

नोडल – Ministry of Social Justice & empowerment

recognition क्योंकि ⇓ Legal Rights ⇓ Rehabilitation (welfare schemes)

→ भारतीय पुनर्वास परिषद Act, 1992 :-

यह परिषद विकलांग जनों के पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के पेशेवरों व कार्मिकों के प्रशिक्षण को मॉनिटर एवं विनियमित करता है, और पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।

Policies :-

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए रा० नीति, 2006
(2) दीनदयाल विकलांग जन पुनर्वास यो०
(3) वि० व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
(4) सहायक उपकरणों की खरीद/उन्हें लगवाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना (ADIP)

विक्र॰ व्यक्ति॰ हेतु रा॰ नीति, 2006 → nodal agency = सामा॰ न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

प्रावधान
→ C - Chief Commis
→ S - State Comm

1) निशक्तता की रोकथाम
(2) पुनर्वास हेतु विशेष कदम
(3) भौतिक पुनर्वास जिसमें आरंभिक पहचान व हस्तक्षेप, परामर्श व चिकित्सीय सुविधा शामिल है :— (निःशक्तों को aware करना by NGO's)
(4) शैक्षणिक स्तर पर पुनर्वास → जिसमें व्यवसायिक प्रशिक्षण शामिल है।
(5) निशक्त व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त (Chief Comissioner) की नियुक्ति C. स्तर पर व S. आयुक्तों की नियुक्ति S. स्तर पर, ताकि यह अपने वैधानिक जिम्मेदारियों के अलावा रा॰ नीति के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका निभा सके।

दीनदयाल विकलांग जन पुनर्वास योजना :—

1) यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसमें शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं। [illegible]
2) 1999 से कार्यान्वित है।
3) Main aim :— NGO के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करना है, तथा PWD Act, 1995 को सुचारु रूप से कार्यान्वित करना है।

1 Jan, 2003 में change → NGO के साथ voluntary org. को शामिल किया गया।)
\+
19 Sub - schemes को शामिल किया गया

ALIMCO (कानपुर)
(भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम) :—

ADIP :
इस योजना में जरूरी उपकरण दिव्यांगों को उपलब्ध कराये जाते हैं, through ALIMCO, Kanpur

निःशक्त जनों के कल्याण हेतु एजेंसियाँ / संस्थाएं

1) भारतीय पुनर्वास परि०
2) दिव्यांग व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त कार्यालय
3) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास
4) NHFDC

12वीं योजना का एजेंडा

- सेवा वितरण में सुधार
- दिव्यांगता अधिकारों हेतु जन जागरूकता का सृजन
- (मसौदा) दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार विधेयक, 2012

services measures to change; for this; NPA, 1995

National trust ने तीन योजनाएं निर्मित

(1) बढ़ते कदम (चलन संबंधी दिव्यांगता जागरूकता अभियान)
(2) निरामय - (स्वास्थ्य बीमा योजना दिव्यांग जनों के लिए)
(3) आस्मिता - इसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों के माता-पिता/संरक्षक हेतु सामूहिक जीवन बीमा योजना

⇒ विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों विधेयक, २०१२

1995 में change

- आरक्षण – 3% से 5%

- साथ ही एक नया विभाग Mini सा॰ न्याय एवं अधिकारिता के तहत होगा, जो कि केवल निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु कार्य करेगा।

Qus ⇒ भूमण्डलीकरण के इस दौर में भारत में निःशक्त व्यक्ति किस प्रकार भारत की आर्थिक संवृद्धि में ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सकते हैं, उदा॰ सहित प्रस्तुत कीजिए।

5yp

9th → welfare आधारित

10 → अधिकार योजना

11 → Inclusive growth

12th → sustainable development + I. G.

भारत में कामगार

facts :- (1) 94% से अधिक कामगार असंगठित क्षेत्र में (ILO रिपोर्ट)

(2) सा० सुरक्षा का अभाव

(3) शोषण व न्यूनतम आय का निम्न स्तर

(4) प्राणघातक रोगों से पीड़ित

असंगठित क्षेत्र की संरचना

- कृषक मजदूर
- सीमेंट फैक्टरी में काम करने वाले लोग
- ईंट के भट्टे
- पटाखों के कारखानों
- बीड़ी उद्योग

- उक्त प्रमुखतः Unorganised क्षेत्र के तहत आते हैं, तथा यहाँ पर काम करने वाले कामगारों की कोई भी नियमित आय तथा सा० सुरक्षा नहीं रहती।
- इसके चलते इन कामगारों को U-O कामगार कहा जाता है।

भारत में कामगारों के अधिकार

संवैधानिक अधिकार :-

A - 14, 15(1)(C), 21, 23, 24, 38, 39, 39-A, 41, 42, 43-A और 47

कानूनी अधिकार :-

- बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) Act, 1986

M.C. Mehta V/s State of Tamilnadu :-

- 1996 में S.C. ने इस केस में यह दिशा - निर्देश जारी किये, कि बाल श्रम रोकने का [illegible]

S. C. हाथ में है, तथा बाल श्रम में लगी बच्चों का कल्याण S.C. एवं नियोक्ता दोनों का दायित्व है। (पुनर्वास)

⇓

इसके बाद → new Fund बनाया गया →

Child Rehabilitation welfare fund :
↳ at centre level

- बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) Act, 1986 →
↳ गुरुपाद स्वामी कमिटी की सिफारिशों पर आधारित

⇓

- यह एक्ट 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने का निषेध करता है।
- तथा अपेक्षाकृत कम खतरनाक कार्यों में बालकों के रोजगार का विनियमन करता है।

why change ⇒ बाल श्रम (नि० एवं विनियमन) संशोधन Act, 2016
bcoz of ⇒ RTE

1) ↳ जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को सभी कार्यों में रोजगार देने का निषेध किया गया है। (no work for below 14)

क्रियान्वयन की जिम्मेदारी - DM की

(2) इस विधेयक में एक नया वर्ग किशोर जोड़ा गया है, जिससे तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो 14 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम आयु का है।

(3) विधेयक के अनुसार - किशोरों के खतरनाक कार्यों में पर रोजगार पर निषेध।

(4) दण्ड प्रावधान और सख्त किये गये हैं।

Maximum child labour
(1) U.P.
(2) A.P.
(3) Raj.
(4) महाराष्ट्र

Child labour के उन्मूलन हेतु भारत Govt. की नीति

⇓

National Child labour Project, 1988

INDUS (InDo-US Child labour welfare scheme)
↳ USA Govt से प्रारंभ
⇓
for Child labour को खत्म

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा Act 2008

- इसके अनुसार केन्द्र स्तर पर रा० सा० सुरक्षा बोर्ड तथा राज्य स्तर पर राज्य सा० सु० बो० के गठन का प्रावधान है।
- इन बोर्ड के कार्य हैं
  - (1) प्रोविडेंट फण्ड तैयार करना
  - (2) कौशल विकास
  - (3) Old age home
- नोडल एजेंसी है श्रम मंत्रालय

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रेता विनियमन) विधेयक, 2012 है।
(1) विक्रय प्रमाण पत्र तथा शहर विक्रय समिति में (town vending comm.) प्रत्येक विक्रेता को पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
(2) 14 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति पथ वि० नहीं बन सकता।

कामगारों के कल्याण हेतु एजेंसियाँ और संस्थान

- I & IInd National Labour Comm
- NSDC (निगम) → P-P
- National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector. (NCEUS)
  ↳ 2004

NSDC

- नॉडल एजेंसी ⇒ F.M
- Excess निवेश
  - Govt (49)
  - Private (51)

NCEUS :-

भारत में अन्य असुरक्षित समूह

- प्रवजक (प्रवासी) कामगार
- सेक्स वर्कर (यौन कर्मी)
- HIV रोगी तथा कैंसर रोगी
- वरिष्ठ नागरिक, पेंशन प्राप्तकर्ता तथा अन्य वृद्धजन
- मादक पदार्थों के उपयोग तथा मद्यपान से प्रभावित व्यक्ति
- पिछड़े तथा अल्पविकसित क्षेत्रों के निवासी
- भिखारी तथा सड़क बच्चे (Street Children), अनाथ तथा बेघर व्यक्ति

भारत में प्रवासन के कारण

1) प्राकृतिक आपदायें
2) नृजातीय संघर्ष → N.E. से पलायन
(3) क्षेत्रीय असमानता
(4) कामगारों की माँग
(5) सुरक्षा
(6) दंगे
(7) कृषि में गिरता सार्वजनिक निवेश

Migrant workers :-

History :- व्यापक रूप से प्रवास ⇒ 1830 started

W.W. - II
- यूरोप
- No अमेरिका

कामगार (Blue Col...)

⇒ भारत में सबसे ज्यादा प्रवासी कामगार ⇒ 1) बिहार 2) उड़ीसा 3) CG 4) झारखण्ड 5) मिजोरम

why ⇒ (1) Land less peop. — (ex – बिहार, उड़ीसा)

(2) Internal Conflict → (ex. 36गढ़, झारखण्ड) → दण्डकारण्य (left wing Extremism)

(3) आधारभूत अवसंरचना (→ मिजोरम)

मुहम्मद ... खान ⇓ IPS

Workers की Prob :–

- Labour Rights →
- Housing की कोई सुविधा } – मलेरिया
- Sanitation

↓

अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें Act, 1979 –

(Interstate Migrant workers (Regulation of Employe-ment & Service Condition) Act, 1979

प्रावधान :–

(1) यह Act उन कामगारों के हितों और जीवन को संरक्षण देता है, जो भारत में अपने गृह राज्य से बाहर सेवा दे रहे हैं।

(2) जब भी कोई नियोक्ता स्थानिय स्तर पर उपलब्ध कामगारों में कौशल की कमी का सामना करता है, तब यह Act राज्य के बाहर उपलब्ध कुशल कामगारों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

⇓

realise → कि उक्त पर्याप्त नहीं → वर्तमान में प्रवास एवं प्रवास कामगारों को रोकने हेतु

I) शहरी गरीबी की रोकथाम

- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SGSRY

II) ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगिण विकास

I) SGSRY ः- started in → 1997
→ केन्द्र प्रायोजित
→ 2009 में पुनर्गठन
→ वर्तमान में इसके 5 मुख्य बिन्दु है०

(1) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम
(2) " महिला स्वयं सहायता कार्य०
(3) " गरीबों में रोजगार के बढ़ावे हेतु दक्षता प्रशिक्षण
(4) " मजदूरी रोजगार कार्य०
(5) " सामुदायिक विकास नेटवर्क

II) PURA ः- (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का लाभ) है
यह योजना P-P-P के तहत है। इसमें ग्रा० विकास विभाग तथा एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता से ग्राम पंचायतों तथा निजि क्षेत्रों की भागीदारी के साथ चलाया जा रहा है।

Scheme ः- उद्देश्य लाभ नहीं
Project → (लाभ को महत्व)
→ अर्थ → 10 वर्ष के लिए निजि क्षेत्र
सामने → ग्रामों का सर्वांगीण विकास
निजि agency मुख्यतः 5 प्रकार की सुविधा ः-

1) जल आपूर्ति
(2) ग्रामीण बाजार
(3) विद्युत ~~वितरण~~
(4) कृषि ~~संबंधी~~ सेवा केन्द्र
(5) जल निकासी

भारत में HIV रोगियों, यौन कर्मियों तथा LGBT समुदायों के लिए भेदभाव व असुरक्षा

- HIV रोगी → २३.१ लाख (लगभग)
- HIV से पीड़ित बच्चे व महिलाएं सर्वाधिक असुरक्षित
- व्यक्तियों के इन समूहों हेतु कोई विधान, कानून अथवा नीतिगत पहल नहीं है।
- यौन कर्मियों का तात्पर्य: उनके मूलभूत मानवाधिकारों से वंचित रहना पड़ता है।
- यौन कर्मियों की यौन संक्रमण (STI) तथा HIV/एड्स की सेवाओं तक पहुँच नहीं है।

(1) नाइजीरिया
(२) S. Africa
(3) India
unofficial data ⇒ 52 लाख

AIDS → HIV → sexual fluid / Blood / Breast Milk

1986 (चेन्नई → Ist case)

Maximum रोगी of Aids ⇒
1) मणिपुर
(२) A.P.
(3) कर्नाटक

सर्वाधिक प्रभावित →
- Orphan Children
- Sex workers
- Injecting Drug user
- Men having sex with men (MSM)

उक्त समूहों से संबंधित एजेंसियां :-

(1) NACO
(२) नाज फाउंडेशन
(3) दरबार महिला समन्वय समिति → कलकत्ता में संगठन → महिला Sex worker हेतु कार्यरत
(4) यौन कर्मियों का अखिल भारतीय नेटवर्क (AINSW)
(5) रा० HIV तथा एड्स नीति और नेटवर्क

NACO :-
- 1992
- Health Ministry के तहत Department
- Duty
  - (1) काउंसलिंग Centre बनाना व AIDS पीड़ित
  - (२) Provide Medical Health

(3) जागरूकता बढ़ाने के उपाय

नाज फाउं.

↳ समलैंगिकों के अधिकार के प्रति कार्यरत NGO

IPC-377

(1) (Homosexual Sex) को वर्जित — इसे दण्ड के दायरे में

→ NGO की याचिका

सहमति से Sex को सही माना

⇒ HC → A-14, 15, 21 का उल्लंघन माना
↳ दण्ड प्रावधान ↓

⇒ राष्ट्रीय HIV तथा एड्स नीति और वर्ल्ड ऑफ वर्क :

↳ श्रम मंत्रा० + स्वास्थ्य मंत्रा० ने सामान्य तरीके से तैयार

↳ यह नीति ILO के कन्वेंशन No - 111 के अंतर्गत तैयार की गई है। (Non discrimination of HIV worker

→ जिसके तहत भारत में किसी भी HIV प्रभावित कामगार उसके कार्यस्थल पर विभेद या प्रताड़ना का सामना ना करने दो।

फिलाडेल्फिया (Non Aids Issue) ↳ (एड्स movie)

भारत में वृद्धजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण Act, 2007
- पेंशन सुधार (स्वावलंबन योजना) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
- रा० वृद्धजन नीति, 1999 --
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए रा० योजना, 2011 (मसौदा)

स्वावलंबन योजना :-

असंगठित क्षेत्रों के लोगों को अपनी सेवा निवृत्ति हेतु स्वैच्छिक रूप से बचत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए तथा इस प्रकार के ग्राहकों हेतु नई पेंशन योजना सरकार द्वारा 26 Sep 2010 को स्वाव० नाम से ...

योजना के रूप में प्रारंभ की गयी थी।

(Co-Contribution)

- यह योजना अंतरिम पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा लागू की जायेगी।
- केन्द्र सरकार एक हजार रु प्रतिवर्ष अपना अंशदान देगी। इस योजना हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक संग्रह कर्ता के रूप में नियुक्त किये गये हैं।

NPS (system)

टियर - I → प्रोविडेन्ट फण्ड से कभी भी पैसा withdraw

टियर - II → निश्चित समय सीमा

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2011 (मसौदा)

(12वीं 5 YP का प्रस्ताव (लक्ष्य)) है -

(1) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक रा० स्तर पर एक रा० वरिष्ठ नागरिक आयोग। तथा राज्य स्तर पर आयोगों की स्थापना की जाये। (राज्य स्तरीय)

(2) एक स्मार्ट ID - कार्ड (for वरिष्ठजन)।

(3) वृद्ध जनों हेतु एक रा० न्यास।

भारत में मद्यपान तथा मादक पदार्थों का दुरुपयोग

(1) मादक पदार्थों की लत + दुरुपयोग गंभीर समस्या। ⇒
भारत के Human Res. दुष्प्रभावित

(2) स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ Act, 1985
तथा (संशोधन) विधेयक, 2011 (Narcotics Drugs & Psycho-tropic substances Act 1985)

उन्मूलन / इलाज → प्रावधान है।

(3) मादक पदार्थों का दुरुपयोग तथा मद्यपान पर नियंत्रण के लिए योजना।

- धारा-71: यह प्रावधान है, कि सरकार अपने विवेकाधिकार से व्यसनियों की पहचान करे उनके उपचार, शिक्षा, पुनर्वास व समाज में पुनः एकीकरण हेतु जितने आवश्यक समझे उतने केन्द्रों की स्थापना करे।

नजरिया
- Education
↓
Treatment
⇓
पुनर्वास → (by Nehru Yuva Kendra) → DM की सुचारु संचालन की जिम्मेदारी
⇓
सामाजिक एकीकरण

संशोधन विधेयक
6 months → सजा
20,000 रु का जुर्माना
का प्रावधान

अन्य imp कार्यक्रम एवं एजेंसियां

(1) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम — 1975 → Ministry of Health

घटक → anti tobacco Prog; जागरूकता अभियान; पुनर्वास के कार्य

(2) राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (National Insti of Social Defence) स्थापना → 15 Jul 2002

(3) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)

मुख्यतः तीन का
हेतु कार्य:
1) परि० नाग
वृद्धजन
2) नशीली दवा
के व्यसनी
(3) प्राणघातक रोग
मरीज

specific Area Prog.

→ Backward Area (250 जिलों की पहचान
↳ इसके लिए Backward Area Regional Grant

→ Border Area

→ Hill Area
↳ असम के दो Dist.

96 District

① कार्बी — आंगलोंग

② नार्थ कछार

↳ तमिलनाडु का नीलगिरी